



7500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास

सिंहस्थ लोक ♦ झाबुआ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झाबुआ में कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में होती है तो लूट करती है, जब सत्ता से बाहर होती है तो लोगों को लड़वाती है। लूट और फूट, यही कांग्रेस की ऑक्सीजन है। रविवार को जनजातीय सम्मेलन में उन्होंने दावा करते हुए कहा कि भाजपा अकेले 370 सीटें ला रही है। 2023 में कांग्रेस की छुट्टी हुई थी, 2024 में सफाया तय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजों से आप पहले ही बता चुके हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए आपका मूड क्या रहने वाला है, इसलिए इस बार विपक्ष के बड़े-बड़े नेता पहले से ही कहने लगे हैं- 2024 में 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सभास्थल पर रथ पर सवार होकर लोगों का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री के रोड शो के लिए अस्थायी गैलरी बनाई गई थी। उन्होंने 7550 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। कुछ प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया। पीएम ने झाबुआ से ही खरगोन में 170 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले टंटया मामा भील विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखी।

प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम में कई रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया और उनकी आधारशिला रखी। इसके तहत रतलाम रेलवे स्टेशन और मेघनगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया जाएगा। राष्ट्र को समर्पित रेल परियोजनाओं में इंदौर-देवास-उजैन सी केबिन रेलवे लाइन के दोहराकरण की परियोजना, इटारसी-याद रीमॉडलिंग के साथ उत्तर-दक्षिण ग्रेड सेपरटर तथा बरखेरा-बुदनी-इटारसी को जोड़ने वाली तीसरी लाइन शामिल है। ये परियोजनाएं रेल अवसंरचना को मजबूत करने तथा यात्री और माल गाड़ियों, दोनों के लिए यात्रा के समय को कम करने में मदद करेंगी।

जनजातीय समाज वोट बैंक नहीं, देश का गौरव

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्ष के दौरान हमारी सरकार आदिवासी समाज के उत्थान, गौरव और सम्मान के लिए समर्पित रही है। हमारे लिए जनजातीय समाज वोट बैंक नहीं, देश का गौरव है। आपका सम्मान भी, और आपका विकास भी, ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वन संपदा कानून में बदलाव करके हमारी सरकार द्वारा आदिवासी समाज को वन भूमि से जुड़े अधिकार लौटाए गए हैं। हमने वोट बैंक के लिए नहीं, आदिवासी समाज के स्वास्थ्य के लिए सिकल सेल एनीमिया के खिलाफ अभियान शुरू किया। आज जो सबसे वंचित है, सबसे पिछड़ा है, हमारी सरकार में वो सबसे पहली प्राथमिकता है। समाज में जो सबसे आखिरी वर्ग होता था, हमने विकास में उसे सबसे पहला दर्जा दिया है।

दो लाख महिलाओं को आहार अनुदान योजना की किशत जारी

प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 559 गांवों के लिए 56 करोड़ रुपये जारी किए। इस राशि का उपयोग आंगनवाड़ी भवन, राशन की दुकानों, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूलों में अतिरिक्त कमरे, आंतरिक सड़कों सहित विभिन्न प्रकार की निर्माण गतिविधियों के लिए किया जाएगा। स्कूल छात्रों को स्मार्ट क्लास, ई-लाइब्रेरी आदि जैसी आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग दो लाख महिला लाभार्थियों को आहार अनुदान योजना की मासिक किस्त का वितरण किया। इस योजना में मध्य प्रदेश की विभिन्न विशेष पिछड़ी जनजातियों की महिलाओं को पीछे आहार के लिए 1500 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाते हैं।

सड़क परियोजनाओं का हुआ लोकार्पण

प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में 3275 करोड़ से अधिक की कई सड़क विकास परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित किया। इसमें एनएच-47 के (हरदा-तेमगांव) 30 किलोमीटर तक हरदा-बैतूल (पैकेज-क) को चार लेन का बनाना; एनएच-752डी का उजैन देवास खंड; एनएच-47 के इंदौर-गुजरात एमपी सीमा खंड को चार लेन (16 किमी) और एनएच-47 के चिचोली-बैतूल, हरदा-बैतूल को चार लेन और एनएच-552जी का उजैन झालावाड़ खंड शामिल है। इन परियोजनाओं से सड़क संपर्क में सुधार होगा और क्षेत्र में आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री अपशिष्ट डंपसाइट उपचार परियोजना, 7 विद्युत सब स्टेशन जैसे अन्य विकास कार्यों का भी शिलान्यास किया।

जनजातीय महासभा में बोले- पीएम नरेंद्र मोदी 2024 में

400 पार



प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को इंदौर विमानतल पर भावभीनी विदाई



प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रविवार को झाबुआ में आयोजित कार्यक्रम के पश्चात इंदौर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिये प्रस्थान किया। इंदौर विमानतल पर उन्हें भावभीनी विदाई दी गयी। नारीय विकास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय तथा जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट विशेष रूप से मौजूद थे। इस अवसर पर सांसद श्री शंकर लालवानी तथा सुश्री कविता पाटीदार, महापौर श्री पुण्यमित्र भार्गव, मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा, महानिदेशक पुलिस श्री सुधीर सक्सेना, विधायक सुश्री ऊषा ठाकुर, श्री रमेश मेंदोला, श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़, श्री मधु वर्मा, श्री मनोज पटेल तथा श्री गोवू शुक्ला, पुलिस आयुक्त श्री मकरंद देउस्कर, कलेक्टर श्री आशीष सिंह सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि गण मौजूद थे।

भगोरिया उत्सव की शुभकामनाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा इंगर देव की जय के उद्घोष के साथ बड़ी संख्या में पधारे जनजातीय समाज को नमन करते हुए कहा कि झाबुआ जितना मध्य प्रदेश से जुड़ा है उतना ही गुजरात से जुड़ा है। झाबुआ के लोगों के दिल भी गुजरात से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि जनजीवन की संस्कृति का उल्लेख करते हुए भगोरिया उत्सव शुभकामनाएं दीं।

आदिवासियों का सम्मान और विकास है हमारी गारंटी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकास के रास्ते पर मध्यप्रदेश तेजी से दौड़ रहा है। पहले यह देश के सबसे बीमार राज्य में गिना जाता था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई की सरकार ने पहली बार जनजातीय समाज के लिए नया मंत्रालय बनाया और बजट का विशेष प्रावधान किया तथा जनजातीय इलाकों और जनजातीय लोगों के विकास को प्राथमिकता दी। मोदी ने कहा कि केन्द्र सरकार ने वन उपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में रिकॉर्ड वृद्धि की। एमएसपी के दायरे में आने वाली वन उपज को 10 से बढ़ाकर 90 तक पहुंचा दिया। देश में वन धन केंद्र खोले ताकि जनजातीय उत्पादों को नए हाट व नए बाजार मिल सकें। जनजातीय समाज देश का गौरव है और देश के उज्वल भविष्य की गारंटी है। जनजातीय लोगों का सम्मान और विकास हमारी गारंटी है। उनके सपने साकार करना सरकार का संकल्प है।

शिक्षा के अभाव में जनजातीय बच्चे पीछे नहीं रहें

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला सरकार ने लिया। टंटया मामा के बलिदान को याद कर आज बलिदान दिवस मनाया जाता है और उन्हीं के नाम पर क्रांतिसूर्य टंटया भील विश्वविद्यालय की घोषणा की जा रही है। मोदी ने जनजातीय समाज के गौरव तिलक मांडवी को याद करते हुए कहा कि उन्होंने 1784 में बिहार के भागलपुर के कमिश्नर को तौर से मार दिया था। आज ऐसे वीर पुरुष की जन्म जयंती है। झाबुआ, रतलाम, खरगोन, धार और आसपास के युवाओं की उच्च शिक्षा आसान होगी। जनजातीय विद्यार्थियों के लिए पूरे देश में एकलव्य आवासीय स्कूल आरंभ किया जा रहे हैं। जनजातीय बच्चे शिक्षा के अभाव में पीछे रह जाए, यह सरकार को स्वीकार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समाज हजारों सालों से वन संपदा से अपनी रोजी-रोटी चला रहा है। पिछली सरकार ने जनजातीय लोगों के अधिकार पर कानूनी पहरे लगा दिए थे। वन संपदा कानून में बदलाव कर केन्द्र सरकार ने जनजातीय समाज को वन भूमि से जुड़े अधिकार लौटाए हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय परिवारों में सिकल सेल एनीमिया हर वर्ष कई लोगों की जान ले रहा था। केन्द्र की सरकार ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए अभियान शुरू किया।

मध्यप्रदेश में डबल इंजन की सरकार डबल तेजी से काम कर रही है

मध्यप्रदेश सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कि डबल इंजन की सरकार कैसे काम करती है

प्रधानमंत्री मोदी ने की क्रांतिसूर्य टंटया भील विश्वविद्यालय की घोषणा

उज्जैन में व्यापार मेला, इन्वेस्टर्स समिट और विक्रमोत्सव 1 मार्च को

ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की दुकानें प्रमुख रूप से लगाई जाएगी...

सिंहस्थ लोक ♦ उज्जैन

व्यापार मेला, इन्वेस्टर्स समिट और विक्रमोत्सव एक मार्च को आयोजित किया जाएगा। व्यापार मेले में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की दुकानें प्रमुख रूप से लगाई जाएगी। इनमें उज्जैन के स्थानीय व्यापारियों को वरीयता दी जा रही है।

उज्जैन में आयोजित व्यापार मेला, विक्रमोत्सव के तहत इन्वेस्टर्स समिट में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्यों के निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा। समिट में गारमेंट्स, टेक्स्टाइल और फूड प्रोसेसिंग यूनिट के जरिये स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार उज्जैन में एक मार्च को विक्रम व्यापार मेला, इन्वेस्टर्स समिट और विक्रमोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इन आयोजनों के लेकर उज्जैन में व्यापक स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। आयोजन की प्रस्तावित गतिविधियों की सूची बनाई जा रही है। इसके साथ ही इन्वेस्टर्स समिट में आमंत्रित उद्योगपतियों और उनकी उद्योग इकाइयों की जानकारी अपडेट की जा रही है।



व्यापार मेला

उज्जैन की विक्रम व्यापार मेले की तैयारियां भी की जा रही हैं। व्यापार मेले का आयोजन नगर निगम उज्जैन द्वारा किया जा रहा है। व्यापार मेले के अन्य सेक्टरों में विभिन्न वस्तुओं के डीलर्स को भी आमंत्रित किया जा रहा है। मेले में नागरिकों के लिये फूड जेन आकर्षण का केंद्र रहेगा। इस जेन में विशेष रूप से मालवा के व्यंजनों का लुत्फ नागरिक उठा सकेगा। व्यापार मेले में पर्यटन, संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के माध्यम से वस्तुओं का प्रदर्शन और बिक्री की जाएगी।

वाणिज्यिक कर विभाग

इलेक्ट्रॉनिक, घरेलू उपकरण और वाहनों की बिक्री पर एसजीएसटी में छूट संबंधी प्रावधान का परीक्षण करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये गए हैं। पर्यटन विभाग महाकाल दर्शन के साथ होटलों में रियायती दर पर रुकने की सुविधा उपलब्ध करायेगा।

स्वच्छता पर विशेष ध्यान

उज्जैन में एक मार्च से होने वाले आयोजनों में नागरिकों के सुविधाजनक आवागमन के साथ व्यापार मेला स्थल पर नगर निगम द्वारा स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन आयोजनों में जन-भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

उज्जैन के इस पार्क में बिना आधार कार्ड नहीं मिलेगी एंट्री, जानें नियम



सिंहस्थ लोक ♦ उज्जैन

बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में कई ऐसे पार्क हैं, जिनमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग अपने मन को शांत करने, ताजी हवा लेने और कुछ वक्त बिताने जाते हैं। कोई अकेले, कोई दोस्तों के साथ तो कोई परिवार के साथ जाकर वहां दुनिया की भाग दौड़ को छोड़कर कुछ पल शांति के बिताता है। वैसे अमूमन तो आपने सुना होगा कि पार्क में जाने के लिए कोई नियम नहीं होते, लेकिन उज्जैन के एक पार्क में जाने के लिए अब लोगों के आधार कार्ड अनिवार्य कर दिए हैं। जिसके पास आधार कार्ड नहीं होगा, उसे पार्क में एंट्री नहीं मिलेगी। अब पार्क में आधार कार्ड चेक किए बिना किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। साथ ही 32 सीसीटीवी कैमरों की मदद से पार्क में आने वाले कपल पर नजर भी रखी जा रही है। पहले पार्क में आने वालों की संख्या 50 से 60 थी। जो अब घटकर 25 से 30 रह गई है।

घटकर आधी हो गई कपल की संख्या

चकोर पार्क में आदेशानुसार आगंतुकों के आधार नंबर रजिस्टर में एंट्री कर प्रवेश दिया जा रहा है। मोबाइल में

आधार कार्ड भी मान्य है। आदेश से पहले रोजाना 60 से 70 कपल पार्क में आते थे, लेकिन अब 25-30 लोग ही आ रहे हैं। यहां 32 सीसीटीवी कैमरों की मदद से पार्क में आने वाले कपल पर नजर भी रखी जा रही है।

असामाजिक तत्वों की पहचान के लिए

महापौर मुकेश टटवाल ने कहा कि पार्क में आए दिन होने वाली घटनाओं से सबक लेते हुए आधार कार्ड से एंट्री को अनिवार्य किया गया है। असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए प्रवेश हेतु आधार कार्ड अनिवार्य किया जाना जरूरी है, जिससे बदमाशी करने वालों की शिनाख्त हो सके।

व्यों पार्क में आधार कार्ड हुआ जरूरी

दरअसल, शहर के मकसी रोड स्थित नगर निगम का चकोर पार्क मौजूद है। यहां पर बड़ी संख्या में युवक और युवतियां घूमने आते हैं। वहीं परिवार के साथ फेमिली के लोग भी पार्क में घूमने के लिए आते हैं। प्रेमी जोड़ों को लेकर अक्सर विवाद देखने को मिलता है। ऐसा व्यवहार ना हो, इसलिए इस गार्डन में आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है।

उज्जैन में एक ही जगह लगेगी सरदार पटेल और अंबेडकर की मूर्ति झड़प के बाद दोनों पक्ष सहमत



सिंहस्थ लोक ♦ उज्जैन

दोनों पक्षों ने फैसला लिया कि माकडौन बस स्टैंड पर सरदार पटेल और बीआर अंबेडकर की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। एसपी शर्मा ने दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों से कहा कि वेमनस्य पैदा करने के लिए जिम्मेदार लोगों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों से कहा गया कि वे मामलों में पुलिस का सहयोग करें।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि पुलिस ने 25 जनवरी की झड़प के सिलसिले में शनिवार तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया और उन पर दंगा करने और एक लोक सेवक को अपना कर्तव्य निभाने से रोकने के लिए आपराधिक बल का उपयोग करने के आरोप में मामला दर्ज किया था।

पुलिस ने कहा था कि घटना का एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसमें कुछ लोग ट्रैक्टर से पटेल की मूर्ति गिरा रहे थे। क्योंकि वे उस स्थान पर अंबेडकर की मूर्ति स्थापित करना चाहते थे। बुधवार देर रात मकडौन बस स्टैंड के पास पटेल की प्रतिमा स्थापित की गई, जिसके बाद झड़प हुई।

मूर्ति स्थापना को लेकर हुए इस विवाद के बाद मौके पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया था और घोर लापरवाही के चलते माकडौन थाना प्रभारी भीम सिंह देवड़ा को निलंबित भी किया था।

महाकाल मंदिर की तर्ज पर चिंतामण गणेश मंदिर प्रबंध समिति अब स्वयं भक्तों को लड्डू प्रसाद उपलब्ध कराएगी। नवगठित समिति की पहली बैठक में इसके सहित कई प्रस्तावों पर मंथन होगा। मंदिर परिसर में वेंडिंग डेस्टिनेशन का प्रस्ताव भी रखा जाएगा।

प्रशासन ने मंदिर समिति में दो नए सदस्यों यशवंत पटेल और रमेश वर्मा को नामांकित किया है। 6 फरवरी, मंगलवार को अपराह्न 3 बजे समिति की बैठक होगी। प्रबंधक अभिषेक शर्मा ने बताया इसमें मंदिर परिसर का विकास करने पर मंथन होगा। मंदिर परिसर में महाकाल मंदिर की तर्ज पर लड्डू प्रसाद मंदिर समिति खुद करेगी। इसमें मंदिर की आय भी बढ़ेगी। मंदिर परिसर में अनेक लोग शादियां करने भी आते हैं।

यहां बिना कुंडली मिलाए शादी की जाती है। इसके लिए पाती के लगन लिखे जाते हैं। इस कारण मंदिर परिसर में ही विवाह का क्रेज भी लोगों में बढ़ता जा रहा है। परिसर को मैरिज डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव भी पारित किया जा सकता है।

अब महाकाल की तर्ज पर चिंतामण गणेश मंदिर में मिलेगा लड्डू प्रसाद!



सिंहस्थ लोक ♦ उज्जैन

नई समिति की पहली बैठक 6 को, वेंडिंग डेस्टिनेशन के प्रस्ताव पर भी होगा मंथन

नई समिति की पहली बैठक 6 को, वेंडिंग डेस्टिनेशन के प्रस्ताव पर भी होगा मंथन

मंदिर परिसर में ही विवाह का क्रेज भी लोगों में बढ़ता जा रहा है। परिसर को मैरिज डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव भी पारित किया जा सकता है।

किया था। इस योजना ने बाद में दम तोड़ दिया, क्योंकि समिति को मेवा से बने लड्डू प्रसाद सांची द्वारा उपलब्ध कराए जाते थे, जो कुछ समय में ही खराब हो जाते थे। इस कारण मोदक प्रसादी काउंटर बंद करना पड़ा। अब समिति स्वयं लड्डू प्रसाद बनवाकर काउंटर पर उपलब्ध कराएगी। चांदी के सिक्कों के विक्रय का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जा सकता है। चिंतामण गणेश मंदिर में शादियों के प्रति लोगों का क्रेज बढ़ता जा रहा है। यहां शादी करने पर खर्च कम आता है और गणेश जी की साक्षी में विवाह होता है। मंदिर परिसर में केवल पांच हजार रुपये से कम में शादी हो जाती है। बिना ताम-झाम के यहां शादी होती है। दिन में ही शादी होती है। इसलिए केवल पूजन-पाठ व मंदिर तथा पंडित के शुल्क के अलावा कोई खर्च नहीं होता। यहां अब राजस्थान, गुजरात व आसपास के अन्य राज्यों के भी लोग आने लगे हैं। यहां गणेश जी की आज्ञा से बिना कुंडली मिलाए पाती के लगन लिखे जाते हैं। विवाह की तिथियों में से कोई एक को अनुकूल लगाती है उस दिन के लगन लिखवा सकते हैं।

मप्र स्काई डाइविंग फेस्टिवल

मप्र को एडवेंचर हब बनाने की पहल स्काई डाइविंग फेस्टिवल 8 से

सिंहस्थ लोक ♦ उज्जैन

प्रदेश में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा 8 फरवरी से स्काई डाइविंग फेस्टिवल की शुरुआत की जाएगी। उज्जैन में 8 फरवरी और खजुराहो में 20 फरवरी से शुरू होने वाला स्काई डाइविंग फेस्टिवल एक बार फिर रोमांच और मनोरंजन की सौगात पेश करेगा।

प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति एवं प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड शिव शंकर शुक्ला ने बताया कि 50 वें खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन होगा। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो में 20 फरवरी से 26 फरवरी तक 50 वें खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन होगा। महोत्सव के स्वर्ण जयंती अवसर को खास बनाने के लिए दुनिया का सबसे रोमांचक खेल स्काई डाइविंग फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। देशभर के रोमांचप्रेमी इस दौरान 10 हजार फीट की ऊंचाई से खजुराहो में पुरातात्विक उत्कृष्टता के प्रतीक धरोहरों को निहार सकेंगे।

उन्होंने बताया कि स्काई-डाइविंग फेस्टिवल के प्रथम एवं द्वितीय संस्करण की सफलता व एडवेंचर गतिविधि के प्रति पर्यटकों के उत्साह को देखते हुए इस वर्ष उज्जैन में तृतीय संस्करण एवं खजुराहो में प्रथम संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। उज्जैन में दताना एयरस्ट्रिप पर 8 से 17



फरवरी तक और खजुराहो में 20 से 25 फरवरी तक एडवेंचर लवर्स असमान में उड़ने के रोमांच का अनुभव कर पाएंगे। स्काई डाइविंग करने का समय सुबह 8 से शाम 5 बजे तक है।

आधुनिक और बेहद सुरक्षित होगी राईड- स्काई डाइविंग का संचालन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन

(डी.जीसीए) एवं यूनाइटेड स्टेट पैराशूट एसोसिएशन यूएसपीए द्वारा प्रमाणित संस्था स्काई-हाई इंडिया द्वारा किया जा रहा है। स्काई डाइविंग में उपयोग किए जाने वाला एयरक्राफ्ट नागरिक विमानन निदेशालय से पंजीकृत है। संस्था द्वारा उच्चतम मानकों के साथ प्रशिक्षित स्काई डाइवर के सहयोग से स्काई डाइविंग कराई जायेगी।

33 हजार में ले सकते स्काई डाइविंग लुप्त- स्काई डाइविंग में भाग लेने के लिये आपको 28 हजार प्लस 18 फीसदी जीएसटी मिलाकर लगभग 33 हजार रुपये खर्च आयेगा। जंप के पहले आपको एक घंटा पहले स्काई डाइविंग के संबंधित ट्रेनिंग दी जायेगी, साथ ही एक वीडियो भी दिखाया जायेगा जिसमें कैसे आप स्काई डाइविंग कर सकते हैं।



उज्जैन-देवास-इंदौर दोहरीकरण के लिए 50 करोड़ मिलेंगे

सिंहस्थ लोक ♦ उज्जैन

उज्जैन वर्ष 2024 के लिए बजट में रेलवे को राशि का आवंटन किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो लिंक के माध्यम से इसकी घोषणा की। इसमें पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल की विभिन्न परियोजनाओं जैसे नई रेल लाइन, दोहरीकरण, आमान परिवर्तन सहित अन्य परियोजनाओं के लिए रेल बजट 2024-25 में राशि आवंटित की गई।

रेलवे पीआरओ खेमराज मीना के अनुसार इंदौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण (79.23 किलोमीटर) के लिए 50 करोड़ रुपए, इंदौर-जबलपुर नई लाइन (345 किलोमीटर) के लिए 1080 करोड़ रुपए, उज्जैन-भोपाल खंड में समपार संख्या 79 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल के लिए 5 करोड़ रुपए, बेड़ावन्त्या-नागदा के बीच समपार संख्या 81 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल के लिए 2 करोड़ रुपए, नागदा-उज्जैन के बीच समपार संख्या 102 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल के लिए 5 करोड़, लक्ष्मीबाई नगर में समपार संख्या 5 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल के लिए 5 करोड़, उज्जैन-भोपाल खंड में मक्सी थार्ड में समपार संख्या 51 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल फोरलेन के लिए 5 करोड़, नागदा थार्ड में समपार संख्या 103 के स्थान पर दो लेन वाले ऊपरी सड़क पुल के लिए 1 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है।

नगर निगम को 24 करोड़ की आय... 88 हजार लोगों ने जमा नहीं किया संपत्तिकर



सिंहस्थ लोक ♦ उज्जैन

नगर निगम को अब तक 24 करोड़ रुपए की आय संपत्तिकर के माध्यम से हो चुकी है, लेकिन 88 हजार करदाताओं तक निगम के अफसर पहुंच ही नहीं सके हैं। निगम प्रशासन जल्द ही इन पर फोकस करेगा। पिछला रिपोर्ट तोड़ने के लिए निगम के पास अब केवल दो माह बचे हैं।

नगर निगम की तंगहाली के बाद भी अच्छी खबर यह है कि जनवरी की स्थिति में पिछले साल की तुलना में निगम खजाने में 24 करोड़ रुपए जमा हो गए हैं। पिछले साल जनवरी तक 23 करोड़ के आसपास आय हुई थी। अधिकारियों की मानें तो पिछले साल के मुकाबले करीब 60 लाख रुपए की आय ज्यादा हुई है, लेकिन पिछले साल 36 करोड़ से ज्यादा की आय हुई थी। इस हिसाब से अभी 12 करोड़ से ज्यादा की आय करने का टारगेट है।

1.30 लाख करदाता, पैसा आया सिर्फ 47 हजार से

बुधवार को एमआईसी सदस्य रजत मेहता ने

संपत्तिकर को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई। इसमें जो आंकड़े सामने आए वे चौंकाने वाले हैं। शहर में 1 लाख 30 हजार के आसपास कर दाता हैं। इनमें से 47 हजार लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी का टैक्स जमा किया, लेकिन करीब 88 हजार लोगों ने टैक्स ही जमा नहीं किया। इससे भी निगम के खजाने पर आर्थिक भार बढ़ रहा।

अधर में कॉम्प्लेक्स, दुकानों का नहीं हो रहा विक्रय

शहर में निगम के नए कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो गए हैं लेकिन इनकी दुकानों का विक्रय नहीं हो पा रहा। इससे भी निगम प्रशासन को आर्थिक मार झेलना पड़ रही। अफसरशाही नगर सरकार पर इतनी हावी है कि महापौर के कहने के बाद भी दुकानों का विक्रय नहीं हो पा रहा।

आय बढ़ाने पर दे रहे जोर

नगर निगम की आय बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं ताकि आर्थिक संकट की स्थिति न रहे। संपत्तिकर वसूली बढ़ाई जाएगी। कॉम्प्लेक्स की दुकान के विक्रय की भी कोशिश कर रहे हैं, जिससे आय हो सके।

-मुकेश टटवाल, महापौर

कोटी पैलेस और परिसर की जमीन पर लेगा आकार

उज्जैन में स्थापित होगा 100 करोड़ रुपए का वीर भारत न्यास, मार्च में शिलान्यास

सिंहस्थ लोक ♦ उज्जैन

महाकाल नगरी उज्जैन में अब 100 करोड़ रुपयों की लागत का वीर भारत न्यास स्थापित करने की तैयारी शुरू हो गई है। विक्रमोत्सव के अंतर्गत 1 मार्च को इसका शिलान्यास किया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर यह कवायद तेज हो गई है। पहले यह न्यास भोपाल में स्थापित करने की योजना थी। न्यास के अंतर्गत दुनिया का पहला ऐसा संग्रहालय होगा जहां भारत के सभी महापुरुषों से जुड़ी मूर्तियां, शिल्प, चित्रकला और साहित्य का संग्रहालय होगा।

कोटी पैलेस और उसके आसपास की जमीन को शामिल कर इस न्यास की स्थापना कर दुनिया का सबसे अलग संग्रहालय बनाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. यादव की पहल पर इस जमीन का चिन्होत्सव कर लिया गया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो विक्रमोत्सव की शुरुआत के साथ ही इसका शिलान्यास भी कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक श्रीराम तिवारी के साथ प्रशासन के अधिकारी जमीन चयन करने की कवायद कर रहे थे। आखिरकार कोटी पैलेस और उसके पीछे की जमीन का चयन इसके लिए किया गया है। इस न्यास के स्थापित होने से देश और दुनिया में उज्जैन की एक अलग पहचान बनेगी।

चौंकाने वाली लंबी कवायद... करोड़ों खर्च पर नहीं खुल सका दफ्तर!



2012-13 में इसकी योजना बनी और उसी साल सैकितिक बजट का आवंटन भी कर दिया गया था। अफसरों ने करीब 100 महान लोगों की एक सूची भी तैयार कर पेश कर दी थी। इनमें धर्म, संस्कृति, ज्योतिष, गणित, विज्ञान जैसे क्षेत्रों की महान विभूतियों के नाम थे। न्यास का दफ्तर नहीं खुला लेकिन संग्रहालय के लिए डेढ़ सौ एकड़ जमीन तलाशने का काम तेज हो गया था। योजना के लिए 2016-17 में 30 लाख रुपए के बजट का प्रावधान किया गया।

27 लाख रुपए का आवंटन हुआ और 27 लाख खर्च भी हो गए। 2017-18 के बजट में वीर भारत योजना के लिए 9 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान हुआ। 8 करोड़ 99 लाख की राशि खर्च भी हो गई। 2018-19 के बजट में भी वीर भारत के लिए 10 करोड़ का बजट आवंटित हुआ। एक करोड़ राजस्व मद में और नौ करोड़ पूंजीगत व्यय में आवंटित किए गए। दोनों मदों में पूरी आवंटित राशि भी खर्च हो गई। 2019-20 के बजट में वीर भारत के लिए करीब साढ़े चार करोड़ का बजट आवंटित किया गया।

यथा है योजना....

भारत को महान या वीर बनाने वालों के जीवन चरित्र लोगों को दिखाने के लिए दिल्ली के अक्षरधाम या आनंदपुर साहेब के विरासत-ए-खालसा संग्रहालय की तर्ज पर संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया गया। इसे नाम दिया गया वीर भारत योजना और प्रस्तावित संस्था को नाम दिया गया वीर भारत न्यास। इसे संस्कृति विभाग की इकाई स्वराज संस्थान संचालनालय से सम्बद्ध कर दिया गया था। पहले इसे भोपाल में बनाने की योजना थी। सीएम डॉ. यादव ने इसे उज्जैन में स्थापित करने का निर्देश दिया है।

योजना अभी प्रारंभिक स्तर पर

अभी यह योजना प्रारंभिक और उच्च स्तर पर है। इसे लेकर विचार चल रहा है।

-नीरजकुमार सिंह, कलेक्टर

नगर निगम ने 'कमाऊपुत' को कर दिया बिना काम का

100 करोड़ की ग्रांड होटल अब पर्यटन विभाग बनाएगा हेरिटेज होटल



सिंहस्थ लोक ♦ उज्जैन

100 करोड़ की ग्रांड होटल जो नगर निगम के लिए कमाऊपुत बन सकती थी, उसे निगम प्रशासन ने बिना काम का कर दिया। अब इसके सहित हेरिटेज होटल का आकार ले रहा महाराजवाड़ा भवन भी मप्र पर्यटन विभाग (टूरिज्म डिपार्टमेंट) को हैंडओवर करने की तैयारी शुरू हो गई है। ग्रांड होटल की करीब 70 करोड़ रुपए की जमीन को बेचने की कोशिशें नाकामयाब होने के बाद अब यह नया यू टर्न आया है।

ग्रांड होटल यूं तो शहर की शान है और रियासतकाल की धरोहर है, लेकिन नगरनिगम की लापरवाही के कारण यह उसके लिए सफेद हाथी साबित हो रही है। निगम अधिकारियों की मानें तो इससे कमाई कम और मटेनेंस पर हर साल करीब 20 लाख रुपए का भार पड़ रहा है। यही कारण है कि तत्कालीन नगर निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता के समय इसकी 10,328 वर्गमीटर जमीन बेचने की तैयारी की गई, लेकिन सरकार ने इस प्रस्ताव को लौटा दिया था। इसके पहले पुनर्जागरण (री-डेवलपमेंट) योजना में विकसित करने की भी योजना बनी, लेकिन वह भी वक्त की आधी में हवा हवाई हो गई।

शुक्रवार को एमपी टूरिज्म विभाग के एमडी डॉ. इलैया राजा टी ने निगम आयुक्त आशीष पाठक के साथ नगर निगम द्वारा संघातित एवं संचालित ग्रांड होटल का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रांड होटल के कमरे, मीटिंग हॉल, लान आदि का निरीक्षण किया और होटल को टूरिज्म विभाग को हैंडओवर कर हेरिटेज होटल के रूप में विकसित कर संचालित करने की संभावनाएं टटोलीं। जल्द ही इस मामले में भोपाल में कोई फैसला हो सकता है। डॉ. राजा ने महाकाल मंदिर के पास महाराजवाड़ा भवन की जगह बन रही हेरिटेज होटल को भी देखा। इसे भी पर्यटन विभाग को हैंडओवर करने की कवायद हो रही है। कुछ समय पहले सीएम डॉ. मोहन यादव

महाराजवाड़ा भवन की हेरिटेज होटल को भी पर्यटन विभाग को देने की तैयारी

महाकाल मंदिर के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने भी आए थे।

बन सकती थी आय का बड़ा स्रोत...

ग्रांड होटल निगम की आय का बड़ा स्रोत बन सकती थी, लेकिन नगर निगम प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। यह होटल शहर के ऐसे स्थान पर है, जहां लोगों को आवागमन में कोई समस्या नहीं आती। शान्ति और मांगलिक कार्यों के लिए यह सबसे अनुकूल जगह है। शहर से करीब 8 किमी दूर की निजी होटलों जमकर कमाई कर रहे

और निगम प्रशासन सिर्फ किराया बढ़ाकर बैठ गया। अगर शान्ति के लिए इसमें अत्याधुनिक सुविधाएं और साज सजा वाले एयरकंडीशंड रूम उपलब्ध करा दिए जाते तो सालाना मोटी कमाई की जा सकती थी। पुराने जमाने के महल जैसी होने के कारण लोगों में आकर्षण भी ज्यादा होता। अफसरों की अनदेखी और जनप्रतिनिधियों की अरुचि के कारण यह होटल एम्बीएम दफ्तर और बैठकों आदि के लिए ही काम आती है। पर्यटन विभाग जब इसे हेरिटेज होटल का रूप देकर कमाई करेगा, तब यह सिद्ध होगा कि निगम के हाथ से कमाऊपुत निकल गया।

80 साल पुराने क्वार्टर्स

होटल परिसर में 28 क्वार्टर हैं, जिनमें नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी रहते हैं। होटल के रखरखाव पर काफी पैसा खर्च होता है। क्वार्टर्स के रखरखाव पर भी निगम को खर्चा उठाना पड़ता है। दो साल पहले नगर निगम ने होटल की जमीन बेचने के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से अनुमति मांगी थी, लेकिन विभाग ने यह फाइल यह कइकर लौटा दी थी कि महापौर परिषद के माध्यम से यह। प्रस्ताव भेजा जाए। परिसर में 10,328 वर्गमीटर जमीन है। कलेक्टर गाइडलाइन की दर 65,600 रुपये प्रति वर्गमीटर के हिसाब से जमीन

की कीमत 67 करोड़ 78 लाख रुपये से ज्यादा है। पूरी प्रॉपर्टी की कीमत 100 करोड़ से ज्यादा है।

ग्रांड होटल परिसर में मैरिज गार्डन, पीछे की ओर करीब 10 हजार वर्ग मीटर जमीन है। इस पर महापौर, निगम अध्यक्ष व निगमायुक्त के बंगलों के साथ ही एक दर्जन से अधिक कर्मचारियों के शासकीय मकान भी हैं। परिसर में 28 आवासीय क्वार्टर हैं। जमीन की बेस प्राइज लगभग 70 करोड़ रुपए आंकी गई है। निगम ग्रांड होटल को 20 साल के लीज पर देने का प्रयास भी कर चुका है।

इसलिए बनी सफेद हाथी...

नगर निगम ग्रांड होटल का संचालन और संभारण करता है। कर्मचारी, बिजली, मटेनेंस आदि पर निगम को प्रति वर्ष करीब 20 लाख रुपए खर्च करना पड़ते हैं। पहले होटल में शादियां होने से अच्छी कमाई भी हो जाती थी, लेकिन बाद में निगम ने इसका किराया बढ़ा दिया तो लोगों ने दूरी बना ली।

महाकाल का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की

सिंहस्थ लोक ♦ उज्जैन

महाकाल मंदिर की फेसबुक साइट पर महाकाल मंदिर के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर उस पर आपत्तिजनक सामग्री डालने का मामला सामने आया है। घटना सामने आने के बाद मंदिर प्रबंध समिति के कर्मचारी ने महाकाल थाने में आवेदन दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

महाकाल मंदिर समिति मंदिर की ऑफिशियल फेसबुक इंस्टाग्राम और वेब साइट को संचालित करके उस पर रोजाना होने वाले कार्यक्रम सहित दर्शन व्यवस्था और फोटो वीडियो अपलोड करती है। अज्ञात आरोपी ने फेसबुक पर महाकालेश्वर मंदिर के नाम पर नया अकाउंट बनाकर उसमें आपत्तिजनक सामग्री डाल दी। इस फर्जी फेसबुक पर उज्जैन निवासी एक भक्त को आपत्तिजनक सामग्री दिखाई दी, तो उसने तत्काल इसकी सूचना महाकाल मंदिर के कंट्रोल रूम पर फोन लगाकर दी। उसने कुछ फोटो और स्क्रीन शॉट भी कंट्रोल रूम को शेयर किए।

इसके बाद महाकाल मंदिर की साइबर शाखा में कार्यरत सीरध नामक व्यक्ति ने पुलिस महाकाल थाने में दिए आवेदन में बताया कि महाकाल मंदिर की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर उस पर अश्लील सामग्री डाली जा रही है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आपत्तिजनक अश्लील पोस्ट किए जाने की सूचना पर से थाना महाकाल पर अपराध क्रमिक 58/24 थारा 188 और 67 आईटी एक्ट में दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।



महाकाल मंदिर की ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफार्म है

महाकाल मंदिर प्रबंध समिति द्वारा बताया गया कि जिस फेसबुक पेज पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की गई है वह फर्जी नाम से बना है। उसका संचालन समिति द्वारा नहीं किया जाता है। उक्त मामले की तकनीकी जानकारी प्राप्त करने और फर्जी फेसबुक पेज को डिलीट करने के लिए नोडल ऑफिसर फेसबुक को मेल किया गया है। मंदिर समिति की ओर से कहा गया कि श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा संचालित ऑफिशियल फेसबुक पेज सुरक्षित है, ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर उज्जैन के नाम से संचालित एक फर्जी फेसबुक पेज पर आपत्तिजनक पोस्ट डाली जा रही है जिसका श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति से कोई संबंध नहीं है।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कर रहा है शैक्षणिक ढांचे में बड़े बदलाव

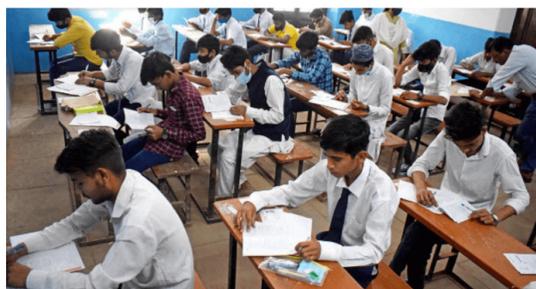
अब 10th में दस तो 12th में पढ़ाए जाएंगे छह विषय, स्कूलों को पत्र जारी...

सिंहस्थ लोक ♦ उज्जैन

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) एनईपी 2020 के तहत नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप के तहत आगामी सत्र से शैक्षणिक ढांचे में बदलाव कर रहा है। इस संबंध में सीबीएसई बोर्ड ने अपने मान्यता प्राप्त स्कूलों को पत्र जारी किया है। बदलाव सत्र 2024-25 से लागू होगा।

सीबीएसई द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के तहत किए जा रहे शैक्षणिक ढांचे में अगले सत्र से 10वीं कक्षा में छात्रों को 10 विषयों की पढ़ाई करनी होगी। जबकि 12वीं कक्षा में छह भाषाएं शामिल होंगी। इन तीन भाषाओं में से छात्रों को दो भारतीय भाषाओं की पढ़ाई करनी अनिवार्य रहेगी। जबकि 12वीं कक्षा में छह भाषाओं की पढ़ाई करनी होगी, जिसमें चार विषय और दो भाषा होंगी। इसमें से भी छात्रों को एक भारतीय भाषा की पढ़ाई करनी जरूरी रहेगी। आगामी सत्र से छात्रों को जेईई की तर्ज पर दो बार बोर्ड परीक्षा का मौका मिलेगा। 10वीं कक्षा में पहले पांच विषय की पढ़ाई थी - सीबीएसई में मौजूदा समय में कक्षा 10 में क्रेडिट आधारित प्रणाली के तहत छात्रों को

पांच विषयों (दो भाषाओं के साथ तीन विषय) की पढ़ाई करनी होती है। इसमें गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन शामिल हैं। लेकिन इसमें बदलाव करते हुए अगले सत्र से 10 विषयों (सात मुख्य विषय और तीन भाषा) की पढ़ाई करनी होगी। तीन भाषाओं में से दो भारतीय भाषा की पढ़ाई करनी जरूरी होगी। जबकि अन्य विषयों में गणित और कम्प्यूटेशनल थिंकिंग यानी कंप्यूटर वैज्ञानिकों की तरह सोचना, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और कल्याण, व्यावसायिक शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा समेत सात प्रमुख विषय हैं। वहीं, कक्षा 11वीं और 12वीं में मौजूदा समय में छात्र पांच विषयों (एक भाषा और चार ऐच्छिक विषय) की



पढ़ाई करते हैं। जबकि कुछ छात्र ऐच्छिक रूप से छह विषय भी पढ़ते हैं, जिसमें एक भाषा और पांच ऐच्छिक विषय होते हैं। लेकिन आगामी सत्र से छात्रों को छह विषय (दो भाषा और चार विषय) की पढ़ाई अनिवार्य रहेगी। इसमें दो भाषा में से एक भारतीय भाषा होनी जरूरी होगी। स्कूलों में पहली बार क्रेडिट सिस्टम : आगामी सत्र से पहली बार स्कूलों में नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के तहत क्रेडिट सिस्टम से पढ़ाई होगी। अभी तक सालभर की परीक्षा के आधार पर अंक मिलते हैं, उसी के आधार पर पास या फेल लिखा जाता है। कक्षा 12वीं से लेकर छठी कक्षा तक सालाना 1200 घंटे की पढ़ाई जरूरी होगी। जबकि पांचवीं में 1000 घंटे और चौथी से लेकर प्री-स्कूल तक सालाना 800 घंटे की पढ़ाई करनी होगी। इसके

अलावा कक्षा 12वीं से लेकर छठी कक्षा तक सालाना 40 क्रेडिट अर्जित करने होंगे। पांचवीं से तीसरी कक्षा तक 30 क्रेडिट और दूसरी कक्षा से प्री-स्कूल 27-27 क्रेडिट लेने होंगे। कक्षा में 75 फीसदी हाजिरी अनिवार्य रहेगी। यदि कोई छात्र 30 घंटे की पढ़ाई करेगा तो उसे एक क्रेडिट अर्जित होगा। कक्षा में एक पीरियड 45 मिनट का रहेगा।

कक्षा दूसरी तक परीक्षा नहीं : एनईपी के तहत तीन से आठ साल तक की आयु के छात्रों का मूल्यांकन पारंपरिक परीक्षा के माध्यम से नहीं होगा। छात्रों के क्लासरूम में लिखने-पढ़ने, सोखने और खेल आदि के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों को भाषा विषय में अब अपनी मातृभाषा में पढ़ने का मौका मिलेगा। दूसरी कक्षा के छात्रों के स्कूल बैग में सिर्फ गणित और भाषा की किताब होगी। इसके अलावा कक्षा में गतिविधियों के माध्यम से बच्चे खेलकूद, वीडियो, संगीत, कहानी बोलने-लिखने, व्यवहार, उम्र के आधार पर लिखने-पढ़ने-समझने की क्षमता सीखेंगे और उसी का मूल्यांकन होगा। प्री स्कूल, नर्सरी, लोअर केजी, अपर प्रेप, प्री -प्राइमरी, केजी व अपर केजी की जगह बालवाटिका एक, दो और तीन होगा। बालवाटिका के लिए भी एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रम तैयार किया हुआ है। इसमें बालवाटिका एक, दो और तीन के छात्रों के लिए कोई स्कूल बैग और किताब नहीं होगी।

सोलर एनर्जी से रोशन होगा शहर....

उज्जैन को क्लीन, ग्रीन, सोलर सिटी बनाने की तैयारी

सिंहस्थ लोक ♦ उज्जैन

शहर में कार्बन उत्सर्जन नियंत्रित करके क्लीन, ग्रीन सिटी के साथ ही सोलर सिटी बनाने की तैयारी की जा रही है। उज्जैन को सोलर सिटी बनाने और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए शीघ्र ही वातावरण निर्माण करने के लिए नागरिकों को अपने आवास की छतों सहित अन्य स्कूल, कॉलेज और शासकीय ऑफिसों में सोलर पैनल लगवाने का जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत कब होगी यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसके लिए विद्युत अधिकारियों को संबंधितों से संपर्क में रहने को कहा गया है, ताकि इस दिशा में कार्ययोजना पर अमल में आसानी हो।

उज्जैन शहर में योजनाबद्ध तरीके से सोलर एनर्जी प्लांट और उपयोग को निर्धारित कर क्रमबद्ध ढंग से जन सहयोग से लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। शहर को सोलर सिटी बनाने और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए शीघ्र ही वातावरण निर्माण

करने के लिए जागरूकता अभियान चलाकर नागरिकों को आवास की छतों सहित अन्य स्कूल, कॉलेज और शासकीय ऑफिसों में सोलर पैनल लगवाने प्रेरित जाएगा। सोलर एनर्जी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक सोलर पैनल लगाने के प्रयास किए जाएंगे।

प्रोजेक्ट और सबसिडी के बारे में बताया जाएगा

अधिकारिक सूत्रों के अनुसार अभियान शासन के विशेषतः ऊर्जा विकास निगम के प्रावधानों, एक से 3 किलोवाट के घरेलू सोलर पैनल के प्रोजेक्ट, अनुदान और सबसिडी आदि की जानकारी दी जाएगी। रहवासी संघों के बीच विशेष अभियान चलाकर प्रतिस्पर्धा को जागृत किया जाएगा। अधिक से अधिक लोगों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। बिजली कंपनी एक दिन में सोलर सिटी के लिए नेट मीटर लगा देगी। बिजली कंपनी की टीम नगर निगम की टीम के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाएगी, वार्डों में प्रजेंटेशन भी दिया जाएगा।



5 साल में यूनिट की लागत वसूल होगी

जानकारों के अनुसार सोलर यूनिट लगाने की लागत पांच साल में वसूल हो जाती है और अगले बीस साल तक मुफ्त बिजली मिल जाती है। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए लोगों को सौर ऊर्जा अपनानी चाहिए।

इनका कहना

शासन की उज्जैन-इंदौर को सोलर सिटी बनाने की योजना प्रस्तावित है। उज्जैन और इंदौर में सोलर सिटी के लिए विद्युत कंपनी के मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता को उपभोक्ताओं, व्यापारियों, उद्योग संघ, शासकीय अधिकारियों आदि से संपर्क में रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि सोलर सिटी की दिशा में कार्ययोजना पर अमल में आसानी रहे।

- अमित तोमर, प्रबंध निदेशक मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी!



सिंहस्थ लोक ♦ उज्जैन

दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मार्च में आयोजित होने वाले विक्रमोत्सव के अंतर्गत इस घड़ी का लोकार्पण करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए करीब 85 फीट ऊंचा वैदिक टॉवर भी बनकर तैयार हो गया है। मध्यप्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है।

उज्जैन पहला ऐसा शहर होगा जहां वैदिक घड़ी के अनुसार समय देखा जा सकेगा। इसके लिए नगर निगम ने 80 फीट ऊंचा टॉवर बनाया है। यह बनकर तैयार हो गया है और रंगरोगन का काम भी पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की उपस्थिति में वैदिक घड़ी के लोकार्पण का कार्यक्रम होगा।

विक्रमोत्सव 1 मार्च से आरंभ होगा और इसके अंतर्गत अनेक कार्यक्रम होंगे। इसी उत्सव के अंतर्गत मार्च के पहले हफ्ते में लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी

चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी वरुणाली इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और लोकार्पण करेंगे। सूत्रों के अनुसार 1 या 4 मार्च को यह कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी चल रही है। 4 मार्च को पीएमओ से हरी झंडी मिलने की संभावना बताई जा रही है। वैदिक घड़ी की स्थापना के साथ ही उज्जैन पूरी दुनिया को वैदिक घड़ी के साथ चलने का संदेश भी देगा।

परिसर का विकास करने की तैयारी

घड़ी स्थापित करने के लिए 85 फीट ऊंचा टॉवर स्थानीय टेकदार अरविंद यादव ने किया है। मार्च में लोकार्पण से पहले टॉवर के आसपास ग्रीनरी विकसित कर इसे पर्यटन केंद्र बनाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। संस्कृति विभाग के अंतर्गत विक्रमदित्य शोधपीठ को यह हैडऑवर किया जा सकता है।

23 करोड़ का ब्रिज बनाएगा नया रिकॉर्ड...?

सिंहस्थ 2016 के लिए हुआ था निर्माण शुरू, सिंहस्थ 2028 में होगा पूरा!

सिंहस्थ लोक ♦ उज्जैन

महाकाल नगरी उज्जैन में 23 करोड़ की लागत से बन रहा ओवरब्रिज देश में एक नया रिकॉर्ड बनाएगा? यह प्रश्न अब क्षेत्रीय लोगों द्वारा उठाया जा रहा है, क्योंकि सिंहस्थ 2016 के बाद से काम शुरू होने के बाद यह अब तक पूरा नहीं हो सका है। संभावना है कि अगले सिंहस्थ 2028 में ही इसे पूरा कर विभाग एक नया रिकॉर्ड बनाएगा।

गुजरात की जिस कंपनी को मोहनपुरा रेलवे क्रॉसिंग (एलसी 23) पर बनाया जा रहा है, उसने हाथ खड़े कर दिए हैं और अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया है। इससे ब्रिज का शेष 20 फीसदी काम अक्षर में पड़ गया है।

बड़ी बात यह कि इतना होने पर भी विभाग के अफसर कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई करने की जगह उस पर मेहरबान नजर आ रहे। सूत्रों के अनुसार

ब्रिज के सफर की कहानी

- निर्माण की शर्तों के अनुसार 2018-19 में पूरा हो जाना चाहिए था।
- गुजरात की अजय प्रो टेक कंपनी को इसका ठेका 2016 में दिया गया था।
- कई बार ब्रिज की प्लानिंग भी बदली गई।
- ठेकेदार कंपनी को कई बार नोटिस दिए, ठेका टर्मिनेट करने की चेतावनी भी दी गई।
- ब्रिज का 20 फीसदी काम अभी भी बाकी।
- जल्द काम पूरा नहीं हुआ तो सिंहस्थ 2028 में पूरा होने के आसार।

विभाग के अफसर बचा काम बैलेंस वर्क के तौर पर किसी दूसरी कंपनी को देने की तैयारी कर रहे। जबकि गुजरात की कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करने जैसी कार्रवाई की जाना चाहिए। मामले में लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग के कार्यपालन यंत्री कुलदीपसिंह भी कोई कदम उठा नहीं सके हैं। मामले में उनसे संपर्क करना चाहा, लेकिन हो

नहीं सका। इस कारण ब्रिज की स्थिति अस्पष्ट बनी हुई है।

अब कलेक्टर करेंगे सवाल जवाब

कलेक्टर नीरजकुमार सिंह ने बताया इस मामले में विभागीय अधिकारियों से बात कर काम को तेजी से पूरा करने का रास्ता निकाला जाएगा।

देरी के तीन बड़े कारण

1. ब्रिज के प्रोजेक्ट में पहले आरई वॉल का प्रावधान था, लेकिन बाद में डिजाइन बदली गई।
2. ब्रिज की ऊंचाई को लेकर भी तकनीकी अड़चने आईं।
3. कोरोना और पैसा समय पर न मिल। पाने से भी काम रुका।

बनते बनते 8 साल गुजर गए

मोहनपुरा ओवरब्रिज को बनते बनते 8 साल गुजर गए, लेकिन अभी भी काम पूरा नहीं हो सका है। जानकारों के अनुसार अभी भी ब्रिज का करीब 20 फीसदी काम अधूरा है। इससे राज्य सरकार की प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है। विधानसभा चुनाव से पहले मोहनपुरा के लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन वह भी बेअसर साबित हो रहा।

घाटों पर 60 लाख से अब सुरक्षा रेलिंग लगेगी

सिंहस्थ लोक ♦ उज्जैन

शिप्रा में नहाने के दौरान श्रद्धालुओं की मौत को रोकने के लिए स्मार्ट सिटी की ओर से लगभग दो साल पहले करीब 13 करोड़ से ज्यादा राशि का प्रावधान कर व्यापक प्लान बनाया गया था। इसमें रामघाट से लेकर सिद्ध आश्रम तक कार्य होना था। प्लान लालफीताशाही और ऑफिसर्स में समन्वय की कमी से फाईल्स में दफन हो गया। 60 लाख से अधिक की लागत से घाटों पर सुरक्षा रेलिंग के लिए नए सिरे से प्रस्ताव मांगे गए हैं।

उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने उज्जैन शहर-3 में शिप्रा नदी के किनारे घाटों पर सुरक्षा रेलिंग की स्थापना के लिए इच्छुक पार्टियों को आमंत्रित किया है। 60 लाख 71 हजार 921 रु. से अधिक के इस कार्य के लिए तकनीकी बिड जमा करने की तिथि



15 फरवरी रखी गई है। यह काम होना था शिप्रा के घाटों पर- रामघाट क्षेत्र में प्लेटफार्म, रेलिंग के साथ में सेपटी

चेन, चॉजिंग रूम का निर्माण, नदी में संकेतक, काले एरन की दीवार, नदी में भी फाउंटन

पूर्व का प्रोजेक्ट ड्राइंग-डिजाइन में झूलाता रहा

शिप्रा में श्रद्धालुओं की मौत को रोकने के लिए दो वर्ष पहले स्मार्ट सिटी की ओर से करीब 13 करोड़ से ज्यादा राशि का प्रावधान किया था। रामघाट पर नदी क्षेत्र में सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट तैयार करवाया था। इसमें स्मार्ट सिटी की ओर से 13.3 करोड़ रुपए मंजूर किए जाकर टेंडर किया था। एजेंसी फिक्स होने के बाद भी ड्राइंग-डिजाइन फाइनल नहीं हो पाने की वजह से कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू नहीं हो पाया। कई दिनों तक प्रोजेक्ट झूलाता रहा। कुछ समय बाद रामघाट क्षेत्र में निर्माण कार्य शुरू हुआ, जो रोक दिया गया है। अधिकारियों में तालमेल नहीं होने की वजह से एक समान प्लेटफार्म बनाने और रेलिंग के साथ में सेपटी चेन लगाने तथा बॉयोटेइलेट के काम में लेटलतीपी होती रही।

उज्जैन कृषि मंडी का ई-एप तैयार, जल्द होगा ऑनलाइन कारोबार



सिंहस्थ लोक ♦ उज्जैन

सरकार की मंशा अनुसार उज्जैन की ए श्रेणी कृषि उपज मंडी में जल्द ही ऑनलाइन ई मंडी व्यवस्था लागू की जा रही है। मंडी का ई-एप तैयार हो गया है। मंडी में जल्द ही ऑनलाइन कारोबार होगा। बड़े तौल कांटे के संचालक के मोबाइल में भी एप रहेगा। किसानों को उपज की भुगतान व्यवस्था भी एप से होगी।

उज्जैन कृषि उपज मंडी जल्द ही ऑनलाइन काम करने लगेगी। व्यापारी, किसान, हम्मालों को कागजी कार्यों से छुटकारा मिल जाएगा। किसान के उपज से भरे वाहन के मंडी गेट से प्रवेश से लेकर नीलामी तक एप के माध्यम काम होगा। उपज की भुगतान व्यवस्था भी एप से ही होगी।

मंडी संचालन की वर्तमान व्यवस्था कागजों पर चल रही है, जिसमें काफी समय लगता है। इसकी गतिमान करने के लिए उज्जैन मंडी को एप के माध्यम से संचालित करने की तैयारी हो गई है। ऑनलाइन ई मंडी व्यवस्था सिस्टम के अनुसार मंडी का एप तैयार हो गया है। इसे मंडी में अपनी उपज लेकर आने वाले

किसानों के एंड्राइड मोबाइल में लोड कर दिया जाएगा।

इससे किसान अपनी प्रवेश पर्ची बना सकेगा। इसका नंबर गेट का कर्मचारी अपने कंप्यूटर में फीड कर लेगा। नीलामी में नीलामकर्ता व अनुबंधकर्ता के पास पीओएस मशीन रहेगी। इसमें किसान की उपज के नीलामी भाव अंकित करेगा, जो किसान के एप में भी अंकित हो जाएगा।

बड़े तौल कांटे के संचालक के मोबाइल में भी एप

बड़े तौल कांटे के संचालक के मोबाइल में भी एप रहेगा। वह किसान की पर्ची के आधार पर तौल का वजन अंकित करेगा, जो किसान के एप में दिखाई देगा। अंत में जिस व्यापारी के यहां उपज बिकी है, उसके मोबाइल में भी मंडी का एप लोड रहेगा, जिसमें किसान का नाम, उपज का वजन, भाव, अमाउंट बिल के रूप में आ जाएगा। व्यापारी को उपज के कुल कीमत से उल्टाई कम कर अपने कंप्यूटर में बिल निकालकर किसान को नकद भुगतान करना है।

सिंहस्थ लोक ♦ उज्जैन

उज्जैन को देवों के देव महादेव की नगरी कहा जाता है। यहां कई ऐसे अनोखे मंदिर हैं जो हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। लोग अक्सर बेतहर जीवन, स्वास्थ्य और आर्थिक तंगी दूर करने की मनोकामना करने के लिए भगवान के मंदिर में जाते हैं, लेकिन उज्जैन में एक ऐसा मंदिर भी है जहां लोग मृत्यु के लिए दीपक जलाने जाते हैं। यहां लोग मोक्ष की कामना करते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में उनकी प्रार्थना कुछ ही घंटों में पूरी हो जाती है।

अनोखा है उज्जैन का धर्मराज चित्रगुप्त मंदिर

उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे रामघाट पर स्थित धर्मराज चित्रगुप्त मंदिर अनोखा है। पंडितों के मुताबिक, यहां पर दर्शन करने मात्र से कष्ट, पाप और कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है। इस मंदिर



का उल्लेख स्कंद पुराण और अग्नि पुराण में किया गया है। इस मंदिर के ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है जिसकी वजह से इसका खासा महत्व है। यह मंदिर

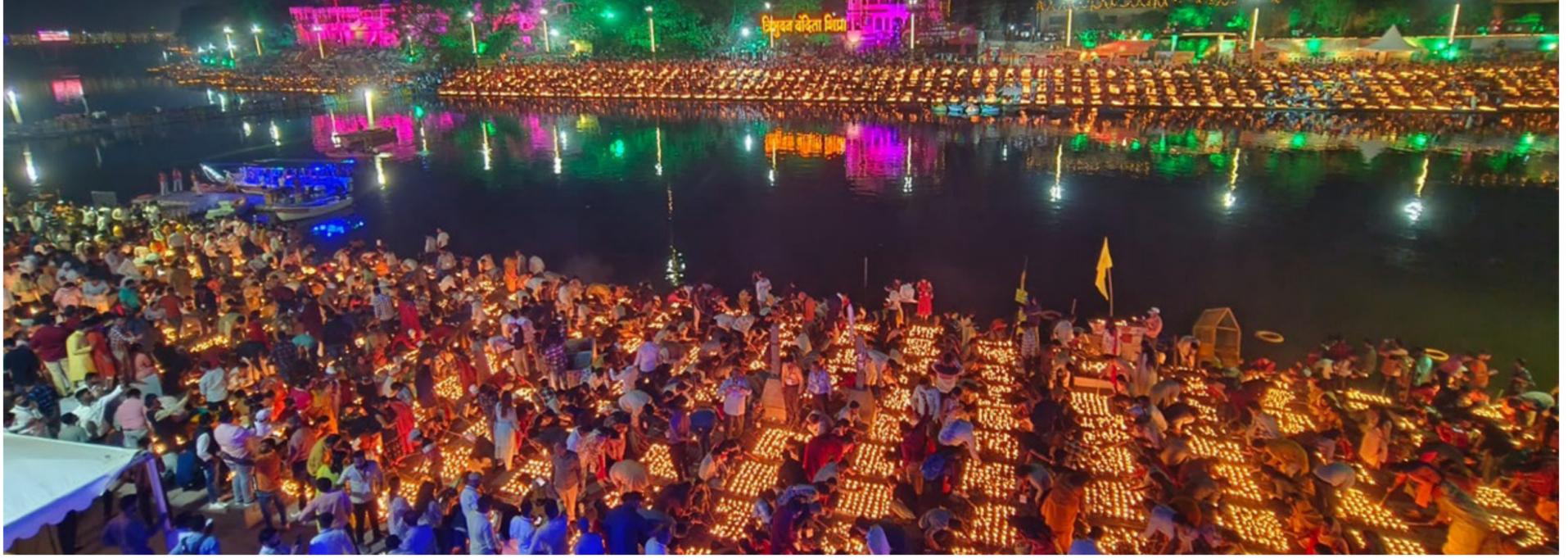
करीब 400 साल पुराना है। यहां श्रद्धालु रोगों से मुक्ति पाने के लिए आते हैं। यहां हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में पूजा करने से

अकाल मृत्यु और भय से मुक्ति मिलती है। 48 घंटे में मिलता है मोक्ष- पंडितों के मुताबिक, इस मंदिर में शारीरिक कष्टों से परेशान जिंदगी और मौत के बीच जूझने वाले व्यक्तियों की रक्षा या मोक्ष की प्राप्ति के लिए खास पूजा करवाई जाती है। मंदिर में पूजा करने 48 घंटों के अंदर रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। यहां पूजा करने से स्वास्थ्य लाभ मिलता है।

मृत्यु के लिए जलाते हैं दीपक- धर्मराज और चित्रगुप्त का ये अनोखा मंदिर अपनी मान्यता के चलते काफी प्रचलित है। कहते हैं कि शारीरिक कष्टों के चलते जिंदगी और मौत से जूझने वाले लोग इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं और यहां रक्षा और मोक्ष की कामना के लिए पूजा करते हैं। कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी लाइलाज है, तो इस मंदिर में आकर अगर वह व्यक्ति अपने मोक्ष के लिए घी का दीपक जलाता है, तो कुछ समय में ही उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और उन सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है।

महाकाल की नगरी में टूटेगा राम की नगरी अयोध्या का रिकॉर्ड, गिनीज बुक में दर्ज होगी यह कामयाबी

30 लाख दीपक होंगे प्रज्वलित



सिंहस्थ लोक ♦ उज्जैन

मध्य प्रदेश की महाकाल की नगरी उज्जैन क्या राम की नगरी अयोध्या में बने दीप प्रज्वलित करने के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ऐसी ही कुछ तैयारी उज्जैन की महाकाल नगरी में की जा रही है। यहां 'शिव ज्योति अर्पण' कार्यक्रम में 30 लाख दीप प्रज्वलित करने की भव्य तैयारी की जा रही है। यह कार्यक्रम उज्जैन में विक्रमोत्सव के दौरान गुड़ी पड़वा पर होगा। उज्जैन के अधिकारी के साथ जनप्रतिनिधि और निगम कर्मचारियों सहित कई कर्मचारी इस कार्य में लगे हुए हैं। गौरतलब है कि साल 2021 में राम की नगरी अयोध्या में 9 लाख 41 हजार 551 दीप प्रज्वलित कर रिकॉर्ड बनाया गया था। इस रिकॉर्ड को साल 2022 में महाकाल की नगरी ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। इस बार दीपोत्सव में 30 लाख के लगभग दीप प्रज्वलित कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया जा रहा है। 30 लाख दीपक एक साथ जलने से अयोध्या का 22 लाख 23 हजार दिए का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा।

उज्जैन की महाकाल नगरी हिन्दू नववर्ष पर आयोजित विक्रम उत्सव में 30 लाख दीपक प्रज्वलित करने का रिकॉर्ड बनाने जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस विक्रम उत्सव को एक माह तक मनाए जाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उत्सव में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जिसमें खास तौर से गुड़ी पड़वा और उज्जैन के गौरव दिवस पर 30 लाख दीपक एक साथ प्रज्वलित किए जाएंगे। एक साथ 30 लाख दीपक जलाने का एक नया विश्व रिकॉर्ड अयोध्या के 22 लाख 23 हजार के रिकॉर्ड को तोड़कर बनेगा। दीपोत्सव को लेकर कलेक्टर ने अधिकारी

जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक की है। इसमें विधायक अनिल जैन कालुहेड़ा, महापौर मुकेश टटवाल, निगमायुक्त आशीष पाठक, यूडीए सीईओ संदीप सोनी मौजूद थे। नगर निगम और स्मार्ट सिटी के सीईओ आशीष पाठक ने बताया कि पिछले वर्ष 18 लाख दीप प्रज्वलित किए थे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व 22 लाख 23 हजार दीपक लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। अब उज्जैन में गौरव दिवस पर दीपोत्सव में इस वर्ष लगभग 30 लाख दीपकों का लक्ष्य किया गया है। दीपक प्रज्वलित करने के इस रिकॉर्ड को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। दीप प्रज्वलन शिप्रा नदी के प्रमुख तटों पर किया जाएगा। इस बार अधिक दीपों के लिए नए सेक्टर की आवश्यकता है। कलेक्टर ने बैठक में दीपोत्सव के लिए अभी से कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। पूरे आयोजन को जीरो वेस्ट रखा गया है। दीप-बाती और तेल को उपयोग में लाया जाएगा।

अयोध्या में बना विश्व रिकॉर्ड श्री राम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत साल 2017 में सीएम आदित्यनाथ यागी की नेतृत्व वाली सरकार ने की थी। इसके शुरुआती दौर में 51 हजार दीपक प्रज्वलित किये गए थे। उसके बाद 2019 में 4 लाख 10 हजार, 2020 में 6 लाख से अधिक जबकि साल 2021 में 9 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित कर रिकॉर्ड बनाया गया था। इसके बाद साल 2022 में 17 लाख 50 हजार दीप प्रज्वलित कर नया रिकॉर्ड बनाया गया। अब महाकाल की नगरी उज्जैन, अयोध्या में बने साल 2023 के रिकॉर्ड को तोड़ने की तैयारी में है। साल 2023 में अयोध्या में 22 लाख

23 हजार दीप प्रज्वलित करने का रिकॉर्ड बना है जो कि गिनीज ऑफ बुक में दर्ज है। महाकाल की नगरी में रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी निगम आयुक्त आशीष पाठक ने बताया कि इस वर्ष गुड़ी पड़वा पर 30 लाख दीपक प्रज्वलित करने का रिकॉर्ड बनाने जा रही है। इसके लिए बैठक कर तैयारी की जा रही है। इस बार अन्य घाटों की आवश्यकता होगी। पूरी महाकाल की नगरी को दीपक से सजाया जाएगा। पिछला जो रिकॉर्ड है वह 18 लाख 36 हजार दीपक प्रज्वलित करने का रिकॉर्ड बनाया गया था। इस बार उससे ज्यादा दीप प्रज्वलित कर अयोध्या में बने रिकॉर्ड को तोड़ने का प्रयास करेंगे। पूरे शहर को सजाया जाएगा। शिप्रा नदी के राम घाट और जो भी अन्य घाट हैं उन सभी जगहों पर दीप प्रज्वलित किए जाएंगे।

सिंहस्थ 2028 की तैयारी

सिंहस्थ का दारोमदार शिप्रा पर सबसे पहले इसका शुद्धिकरण होगा



सिंहस्थ लोक ♦ उज्जैन

सिंहस्थ-28 को लेकर उज्जैन के साथ ही आसपास के सभी जिलों में प्रारंभिक तैयारी शुरू हो गई है। आयोजन का मुख्य दारोमदार शिप्रा नदी पर है, इसलिए सबसे पहले इसके शुद्धिकरण का लक्ष्य रखा गया है। नदी को स्वच्छ व निर्मल करने के साथ ही शिप्रा पर शनि मंदिर से बडनगर रोड तक 28 किलोमीटर के घाट तैयार होंगे। दो-तीन जगह नए ब्रिज भी बनाए जाएंगे। सिंहस्थ तैयारियों को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने शनिवार को फिर उज्जैन से बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक में उज्जैन व इंदौर संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर शामिल हुए। डॉ. राजौरा ने कहा, सिंहस्थ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। उज्जैन के बाद वे खंडवा, महेश्वर, ममलेश्वर, पशुपतिनाथ, बगलामुखी मंदिर जाते हैं। इसलिए इन जिलों में श्रद्धालुओं के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया हों। अभी से से सड़क, पुल, पुलिया, पेयजल, छाया, रूकने के लिए आश्रय स्थल, पार्किंग आदि की व्यवस्थाएं ठीक की जाएं। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक धरोहरें हैं। उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है। अतः सभी सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण करें और जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है उसका पुनर्निर्माण करें। सिंहस्थ के लिए घाट, चौराहा आदि के सौंदर्यकरण कार्य स्याई हों और आगामी बारह वर्ष तक चलें। उन्होंने कहा, शिप्रा शुद्ध हो, क्योंकि सिंहस्थ का सारा दारोमदार शिप्रा नदी पर ही टीका है। देश-विदेश से श्रद्धालु

शिप्रा में स्नान करते हैं। इसलिए शिप्रा का जल निर्मल व आचमन योग्य हो। बैठक में संभागायुक्त डॉ. संजय गोयल, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, जिला पंचायत सीईओ मुगाल मीना, निगमायुक्त आशीष पाठक, यूडीए सीईओ संदीप सोनी मौजूद थे। जहां घाट नहीं, वहां नए घाट बनेंगे- बैठक में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया, सिंहस्थ के मास्टर प्लान (शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स) में सड़क व घाटों की कनेक्टिविटी, प्रमुख मंदिरों में आने-जाने के लिए कनेक्टिविटी, सौंदर्यकरण, पार्किंग मुख्य कार्य हैं, जो प्राथमिकता से किए जायेंगे। विभिन्न अखाड़ों से बात कर धर्मशाला बनाने व 28 किलोमीटर शनि मंदिर से बडनगर तक रोड तक जहां घाट नहीं है, वहां घाट निर्माण होगा। किस जिले में क्या योजना

खंडवा जिला- शिप्रा पर पुल, सदाबल में हेलीपैड, चौरासी महादेव पर लैंड स्केपिंग, प्रवचन हॉल, कालभैरव व मंगलनाथ मंदिर में अन्य निर्माण। लड्डू प्रसाद युनिट की महाकाल मंदिर के निकट स्थापना। हरसिद्धि व चिन्तामन गणेश मंदिर का विकास। कर्कराज मंदिर में पार्किंग का प्रस्ताव शासन को भेजेंगे। पंचक्रोशी मार्ग पर पौधारोपण। बड़े ऑडिटोरियम का निर्माण, हरिफाटक ब्रिज के नजदीक फुट ब्रिज का निर्माण। आरओबी, उज्जैन का चौड़ीकरण, हरिफाटक ब्रिज का चौड़ीकरण, उज्जैन फोरलेन का चौड़ीकरण, इंगोरिया मार्ग का चौड़ीकरण, लालपुल से दताना, चंद्रखेड़ी आदि का चौड़ीकरण, पंचक्रोशी मार्ग को टूलें करने, उज्जैन-तराना-मांगलिया मार्ग का उन्नयनीकरण, सिंकदरी से जीवनखेड़ी-शनि मंदिर तक जाने वाले वैकल्पिक मार्ग का चौड़ीकरण, रूद्रसागर पर रोप-वे स्टेशन, पंचक्रोशी मार्ग पर पड़वा स्थलों पर ट्यूबवेल, पानी की टंकी, स्वच्छता के कार्य। कचरा डिस्पोजल करने और ट्रेनिंग ग्राउण्ड बनाएंगे। श्रद्धालुओं को ठहराने छात्रावास भवन का निर्माण व विश्राम गृह विस्तारीकरण। डॉ. राजौरा ने पुलिस लाइन में स्थाई कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिए। सात चौराहों को इंटीलेजेंट ट्रैफिक चौराहा के रूप में डेवलप किया जाएगा। इंदौर जिला- गौतमपुरा, सांवेर, बेटमा में बसस्टेण्ड। स्वच्छ पेयजल के लिए संचार में व बेटमा में पृथक से व्यवस्था। खरगोन जिला- महेश्वर, मण्डलेश्वर मंदिर में 19.57 करोड़ के सौंदर्यकरण कार्य। बड़वाह पर ओवरब्रिज, धामनोद से बड़वाह रोड, महेश्वर से मण्डलेश्वर के बीच बायपास रोड बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। महेश्वर से बारदोरी तक 6.5 किलोमीटर रोड का चौड़ीकरण, बड़वाह महेश्वर व मण्डलेश्वर में स्थाई हेलीपैड। महेश्वर में रेन बसेरा, कर्म्युनिटी हॉल निर्माण। 35 करोड़ से घाटों का सौंदर्यकरण। खंडवा जिला- ममलेश्वर मंदिर में सौंदर्यकरण, सिद्धकूट से कैलाश मंदिर तक रोड कनेक्टिविटी। मोरटका के अलावा दूसरे वैकल्पिक मार्ग का निर्माण होगा। देवास जिला सिंहस्थ के दौरान जिले में 366 करोड़ के निर्माण कराएंगे। इनमें मंदिर की साज-सजा, श्रद्धालुओं को रूकने के लिए विशेष फोकस रहेगा। परिक्रमा पथ का चौड़ीकरण, शिप्रा शुद्धिकरण अंतर्गत मेंढकी नाला में स्टापडेम निर्माण।

उज्जैन में शिप्रा के आसपास 28 किमी में घाट बनाए जाएंगे



सिंहस्थ लोक ♦ उज्जैन

सिंहस्थ 2028 की तैयारियों में तेजी आती दिखाई दे रही है। करीब 14 करोड़ श्रद्धालुओं की मेजबानी के हिसाब से उज्जैन सहित आसपास के जिलों में भी करोड़ों के विकास के कार्य होने जा रहे हैं। उज्जैन में शिप्रा के आसपास करीब 28 किमी लंबाई में घाट बनाए जाएंगे। खरगोन जिले के बड़वाह-महेश्वर व मंडलेश्वर में स्थाई हेलीपैड बनेंगे। देवास जिले में शिप्रा में सात बैराज का निर्माण होगा और शाजापुर जिले में बेरछा-मक्सी

मार्ग को टू लेन किया जाएगा। इसके अलावा भी उज्जैन व आसपास के सभी जिलों में साधु-संतों तथा श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखकर स्थाई व अस्थायी प्रवृत्ति के कई तरह के काम होंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने शनिवार को सिंहस्थ के लिए किए जा रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की। इसमें वीसी के माध्यम से उज्जैन व इंदौर संभाग के जिलों के सभी कलेक्टर जुड़े हुए थे। डॉ. राजौरा ने शिप्रा नदी के शुद्धिकरण की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि शिप्रा शुद्ध हो, क्योंकि सिंहस्थ का

सारा दारोमदार इसी पर ही टीका है। अतः शिप्रा का जल निर्मल एवं आचमन योग्य हो। उन्होंने यह भी कहा कि जो जिले महाकाल लोक की तरह देवी लोक बनाना चाहते हैं, वे उसका कार्य सिंहस्थ से पहले पूरा कर लें। साथ ही जो जिले धर्मशाला का निर्माण कर रहे हैं, वे यह सुनिश्चित करें कि उसे कोई ट्रस्ट या मंदिर समिति संचालित करें। इनके अलावा डॉ. राजौरा ने सभी कलेक्टरों को ये भी कहा कि वे अपने-अपने जिलों में सांस्कृतिक धरोहरों को संभालकर रखें, जीर्ण-शीर्ण हो रही धरोहरों को पुनः संवारें।

राजस्व मामलों के निराकरण में कई जिले फिसट्टी

उज्जैन जिले में सीमांकन करने की परफार्मेंस कमजोर

सिंहस्थ लोक ♦ उज्जैन

राजस्व मामलों के निराकरण के लिए 29 फरवरी तक चलाए जा रहे महाभियान में शुरुआती 16 दिनों में बड़े जिलों इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा, सागर, उज्जैन की परफार्मेंस कमजोर आई है। कोडं भी बड़ा जिला नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा और राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त करने में प्रथम तीन स्थानों में शामिल नहीं हो सका है। इस बीच विभाग के मंत्री करणसिंह वर्मा ने कहा है कि 30 दिनों से अधिक समय तक केस पेंडिंग रहे तो इसके लिए तहसीलदार और नायब तहसीलदार जिम्मेदार होंगे और उन पर कार्यवाही भी जाएगी। प्रदेश में 15 जनवरी से शुरू हुए राजस्व महाअभियान में अब तक एक लाख 24 हजार राजस्व प्रकरणों का निराकरण हुआ है। इसमें समय-सीमा पार कर चुके नामांतरण, बंटवारा,



सीमांकन और अभिलेख दुरुस्त करने के 244352 प्रकरणों का निराकरण किया जाना है। इसमें तेजी लाने के लिए राजस्व मंत्री करणसिंह वर्मा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जिला और संभाग स्तर पर पहुंचकर महाअभियान की गतिविधियों की स्वयं समीक्षा कर रहे हैं। राजस्व महाअभियान के दौरान दर्ज प्रकरण के निराकरण की कार्यवाही की जा रही है। इसके

लिए महाअभियान डैशबोर्ड का संचालन राजस्व विभाग द्वारा किया जा रहा है जिससे राज्य, जिला और तहसील स्तर पर अभियान के दौरान हो रहे कार्यों की प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है। पेंडिंग केस संख्या के आधार पर यह है स्थिति अभिलेख दुरुस्ती के लंबित 26697 प्रकरणों में से 4554 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। इसमें खंडवा 52 प्रतिशत, अलीराजपुर 50, उज्जैन 50, छिंदवाड़ा और सीहोर ने लंबित 45 प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण किया है। 31 जनवरी तक कुल प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा में नामांतरण के समय-सीमा पार कर लंबित 154595 प्रकरणों में से महाअभियान के दौरान 89718 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। इसमें सीहोर और शिवपुरी ने 88 प्रतिशत, अनूपपुर ने 83, देवास और ग्वालियर ने 78 प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण किया है।

सड़क पर किसान

केंद्र संवेदनशीलता से निकाले समाधान

यदि राजनीति और अन्य दुराग्रहों को नजरअंदाज कर दें तो देश के लिये अन्न उगाने वाले किसानों का अपनी मांगों के लिये सड़क पर आना दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जायेगा। भले ही 2020-21 में हुए लंबे किसान आंदोलन के दौरान होने वाली हिंसक घटनाओं और लाल किले प्रकरण के मद्देनजर केंद्र व हरियाणा सरकार सख्ती दिखा रही हो, लेकिन फिर किसानों के लिये मार्ग में भारी-भरकम अवरोध लगाने और किले बिछाने की कार्रवाई को अच्छा नहीं कहा जा सकता है। निस्संदेह, प्रशासन के सामने कानून-व्यवस्था का प्रश्न होता है और ऐसे आंदोलन के दौरान अराजक तत्वों की दखल का अंदेश बना रहता है। आम नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर ऐसे उपाय जरूरी हो सकते हैं मगर सवाल यह है कि ऐसी स्थिति आती ही क्यों है? समय रहते किसानों के जायज मुद्दों पर संवेदनशील पहल क्यों नहीं होती। तीन कृषि कानूनों के विरोध में लंबे चले आंदोलन के बाद हुए समझौते से जुड़े मुद्दों पर अमल के लिये केंद्र सरकार के पास पर्याप्त समय था। बेहतर होता कि कुछ मांगों को पूरा करने पर पहल होती। जैसे सरकार की दलील रही है कि इतने बड़े देश में हर फसल को एमएस्पी के दायरे में लाना व्यावहारिक न होगा और उसका अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद हम स्वीकारें कि आज खेती घाटे का सौदा बन गई है। किसानों की आत्महत्या को इससे जोड़कर देखा जाना चाहिए। नई पीढ़ी अब खेती से कतराने लगी है। निस्संदेह, भारतीय खेती का स्वरूप विशुद्ध व्यावसायिक नहीं रहा है, लेकिन हमें याद रहे कि देश की करीब आधी आबादी प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर पर खेती व उससे जुड़े व्यवसायों पर निर्भर है। अतः खेती को लाभकारी बनाने की जरूरत है। कोई भीच का रास्ता किसान असंतोष को दूर करने के लिये उठाया जा सकता है। दरअसल, किसान आंदोलनकारी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने, खेतिहर मजदूरों के लिये पेंशन, कृषि ऋण माफी, डब्ल्यूटीए से हटने, किसानों पर दर्ल मुकदमों वापस लेने, लखीमपुर खीरी कांड के पीड़ितों को आर्थिक मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। विडंबना है कि आंदोलन की शुरुआत से पहले किसानों से केंद्रीय मंत्रियों की मंत्रावन वार्ता बेनतीजा रही। जिसके बाद किसान नेताओं ने दिल्ली कूच करने के फैसले को अंतिम रूप दिया। दरअसल, किसान भी जानते हैं कि देश में जब आम चुनाव सिर पर हैं तो केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिये कानून बनाने का उनका सबल आग्रह है। निस्संदेह, किसी भी संगठन को आंदोलन करने का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन प्रयास होना चाहिए कि आंदोलन हिंसक रूप न ले और आंदोलन योजनाबद्ध ढंग से तार्किक परिणति तक पहुंचे। किसानों के मुद्दे अपनी जगह हैं लेकिन किसानों को रोकने के लिये सरकारों द्वारा की गई वृहद् रचना से आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद पड़ी हैं। शासन-प्रशासन ने यात्रियों के लिये जो वैकल्पिक मार्ग तय किये हैं, यात्री उनमें भटक रहे हैं।

लोकसभा चुनाव से पहले आदिवासियों पर डोरे डालते नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी!

लोकसभा

के लिए चुनावी नगाड़े धीरे-धीरे बजने लगे हैं और फिलहाल दो बड़े गठबंधन एनडीए और इंडिया अपने-अपने कुनबे को साधने के साथ ही एक-दूसरे में संभमारी करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, चंपई सोरेन तथा हेमंत सोरेन का प्रयास आदिवासी मतदाताओं को अधिक से अधिक अपने साथ करने का है और इसमें कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। जहां इंडिया गठबंधन झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और चंपई सोरेन सरकार के द्वारा विश्वास मत हासिल करने के बाद आदिवासी अंचलों में भाजपा और नरेंद्र मोदी पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाते हुए आदिवासियों को अपने पाले में लाने का हस्तक्षेप प्रयास करेंगे।

दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों के हित में अनेक योजनाओं की सौगात देने के साथ ही मध्यप्रदेश के झाबुआ से 11 फरवरी को लोकसभा चुनाव प्रचार का आगाज किया। यह इलाका आदिवासी बाहुल्य है और यहां के आदिवासियों पर अपेक्षाकृत कांग्रेस की फकड़ ज्यादा मजबूत है। देश के कई राज्यों में अनेक लोकसभा क्षेत्रों में आदिवासियों का अच्छा-खासा प्रभाव है इसलिए ये दल आदिवासियों को लुभाने में प्राण-पण से जुट गए हैं।

झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने आदिवासी इलाकों में एक आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मामला जोरशोर से उठाते हुए इसे आदिवासी समाज के साथ अन्याय निरूपित किया है। इस मामले को प्रमुखता से उठाते हुए दोनों दल आदिवासियों को अपने पक्ष मोड़ने का हस्तक्षेप प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ एक आदिवासी प्रधान राज्य है और भाजपा ने वहां एक आदिवासी विधुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया है। उसका दावा है कि पहली बार किसी ठेठ आदिवासी को राज्य की कमान सौंपी गयी है। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी अपने आपको छत्तीसगढ़ की दाई का बेटा कहते हुए आदिवासी होने का दावा करते थे जबकि उनके पिता सतनामी थे और जोगी ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। उनकी जाति को लेकर भी कई बार विवाद उठता रहता था, लेकिन विधुदेव साय के आदिवासी होने पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है।

उधर, मध्यप्रदेश के आदिवासी बाहुल्य झाबुआ में 11 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजाति सम्मेलन सम्मेलन में शामिल होकर लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान का आगाज किया। इस जनजाति सम्मेलन के जरिये मध्यप्रदेश और गुजरात के आदिवासी वोट बैंक को सीधे-सीधे साधने का भाजपा प्रयास किया। वहीं पूरे देश के आदिवासी समाज को संदेश देते हुए उन्हें भी अपने पाले में लाने की हर संभव कोशिश भी की।

ऐसा माना जा रहा है कि झाबुआ की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासियों को लेकर कुछ बड़ी एवं महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकते हैं। भाजपा उनकी उपस्थिति का किस प्रकार का राजनीतिक लाभ लेना



चाहती है इसका अंदाजा मध्यप्रदेश भाजपा अध्यक्ष सोंसद विष्णुदत्त शर्मा के द्वारा कार्यक्रमों सम्मेलन में कही गई इन बातों से लगाया जा सकता है कि जब हम झाबुआ आ रहे थे तो वहां हर घर पर भगवा दिखायी दे रहा था, उसी तरह 11 फरवरी को जनजाति सम्मेलन में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आये तब हर मन भी भगवा नजर आना चाहिये।

चुनाव अभियान में अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का भी पूरा लाभ भाजपा को ही मिले इस उद्देश्य से शर्मा ने कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाबुआ आ रहे हैं और यह हमारा सौभाग्य है कि एक रैली से लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के चुनाव अभियान की वे शुरुआत करेंगे। भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि हमें प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत गौरवशाली परम्पराओं और संस्कृति के अनुरूप करना है। स्वागत के लिए जनजाति संस्कृति के प्रतीकों डोल, फालिया, तीर-कमान आदि का प्रयोग होना चाहिए।

चंपई सोरेन ने जीता विश्वास मत

झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में 5 फरवरी 2024 सोमवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने आसानी से बहुमत साबित कर दिया। विश्वास मत के पक्ष में 47 और विपक्ष में 29 मत पड़े, इस प्रकार पहली अंतिम परीक्षा में चंपई सोरेन सफल रहे। इस प्रकार गठबंधन

सरकार के समर्थकों में संघ लगाने में विपक्ष (भाजपा) पूरी तरह विफल रहा। हेमंत सोरेन ने इस प्रस्ताव पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा, केंद्र सरकार और इंडी पर खुद को (हेमंत सोरेन) को झूठे आरोपों में षडयंत्र रचकर फसाने का आरोप लगाते हुए चुनौती के लहजे में उन्होंने कहा कि अगर उनके विरुद्ध साढ़े आठ एकड़ जमीन के घोटाले का आरोप सिद्ध हो गया तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। चर्चा के दौरान हेमंत सोरेन का लहजा तल्लूखी से भरा हुआ था और उन्होंने राज्यपाल पर भी गंभीर आरोप लगाये। उनका कहना था कि 31 जनवरी 2024 का दिन लोकतंत्र के काले दिन के रूप में याद किया जायेगा, उस दिन पहली बार किसी मुख्यमंत्री की राजभवन के अंदर गिरफ्तारी हुई। मुझे लगता है कि मेरी गिरफ्तारी के षडयंत्र में राजभवन भी शामिल था।

हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं आंसू नहीं बहाने वाला हूँ, आपके लिए आदिवासियों के आंसुओं का मोल नहीं है, मैं सही समय पर मुंहतोड़ जवाब दूंगा। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की वर्तमान सरकार के दौर में आदिवासी व दलित सुरक्षित नहीं हैं। इसको देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आदिवासियों और दलितों को लामबंद करने के लिए इंडिया महागठबंधन की राजनीति क्या होने वाली है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने निशाने पर भी भाजपा ही थी और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तारीफों के पुल बांध दिये। उन्होंने कहा कि हमारा शासन काल हेमंत पार्ट-2 है, हां हम हेमंत पार्ट-2 है, हेमंत बाबू हैं तो हिममत है।

और यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास इन दिनों हिमालयीन उछाल मार रहा है। उन्होंने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए दावा किया कि अबकी बार 400 पार। मोदी ने कहा कि आमतौर पर मैं आंकड़ों में नहीं पड़ता लेकिन देश का मिजाज देख रहा हूँ और यह मिजाज आने वाले लोकसभा चुनाव में एनडीए को 400 पार ले जायेगा तथा भाजपा को 370 सीट तक ले जायेगा। अपने 2 घंटे के भाषण में नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा तीसरा कार्यकाल सौ-सवा सौ दिन दूर है और तीसरा कार्यकाल अगले एक हजार साल के लिए मजबूत नींव रखने का कालखंड होगा।

कांग्रेस को अपने निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग 2014 में कहते थे कि 2044 तक दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बनेगा, ये लोग सपना देखने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाये। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि तीस साल नहीं लगेंगे मोदी की गारंटी है मेरे तीसरे कार्यकाल में देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। हमने गरीबों के लिए दस साल में चार करोड़ घर बनाये, कांग्रेस को सौ साल लग जाते। बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि एक प्रोडक्ट बार-बार लांच करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान बंद होने की नौबत आ गयी है। राजनीति में एक परिवार से दस आयें ठीक नहीं है लेकिन एक परिवार ही पार्टी चलाये यह ठीक नहीं है। - अरुण पटेल

रणजी ट्रॉफी के बीच वरुण आरोन ने किया संन्यास का ऐलान

लंबे समय से नहीं मिला मौका



भारत के पूर्व तेज गेंदबाज वरुण आरोन झारखंड और राजस्थान के बीच चल रहे रणजी ट्रॉफी मैच के बाद लाल गेंद क्रिकेट को अलविदा कहेंगे, लेकिन फिलहाल सफेद गेंद क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे। रेड-बॉल क्रिकेट में वरुण आरोन की यात्रा 2008 में शुरू हुई जब उन्होंने जम्मू-कश्मीर के खिलाफ रणजी ट्रॉफी लीग मैच में झारखंड के लिए प्रथम श्रेणी में डेब्यू किया। उनकी तेज गति और प्रतिभा ने उन्हें जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचा दिया। उन्होंने 2011 में वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में भारत के लिए डेब्यू किया। एक महीने बाद, उन्होंने उसी स्थान पर वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में भी डेब्यू किया। वरुण आरोन ने कहा, 'मैं 2008 से रेड बॉल क्रिकेट खेल रहा हूँ। चूंकि मैंने तेज गेंदबाजी की, इसलिए मुझे कई चोटें लगीं। अब मैं समझता हूँ कि मेरा शरीर मुझे रेड बॉल क्रिकेट में तेज गेंदबाजी जारी रखने की इजाजत नहीं देगा, इसलिए मैंने इसे छोड़ने का फैसला किया है।

वरुण आरोन ने कहा, 'यह मेरे परिवार और जमशेदपुर के लोगों के सामने मेरा आखिरी मैच हो सकता है, क्योंकि हम अक्सर यहां सफेद गेंद मैच नहीं खेलते हैं। मैंने अपना करियर यहीं से शुरू किया था, इसलिए यह मेरे लिए काफी भावनात्मक है।

चोटों के कारण कई असफलताओं को सहने के बावजूद आरोन का जूनून अटूट रहा। उनकी आक्रामक गेंदबाजी शैली ने क्रिकेट जगत पर अनमिट छाप छोड़ी, जिसमें इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्राड को खतरनाक बाउंसर जैसे यादगार क्षण शामिल हैं, जिससे 2014 में ओल्ड ट्रैफर्ड में एक टेस्ट मैच के दौरान ब्राड की नाक टूट गई थी। भारत के साथ उनका करियर 2015 में समाप्त हो गया। हालांकि, उस दौरान उन्होंने नौ टेस्ट (52.61 पर 18 विकेट) और नौ वनडे (38.09 पर 11 विकेट) खेले। अपने 65 प्रथम श्रेणी मैचों में, उन्होंने 33.74 की औसत से 168 विकेट लिए। आरोन को इंग्लिश काउंटी सर्किट में डरहम के लिए खेलने का भी मौका मिला। क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने की दौड़ से बाहर हो चुके झारखंड के लिए यह रणजी सीजन का आखिरी मैच होगा।

न्यूजीलैंड को बड़ा झटका, चोट के चलते 6 महीने के लिए बाहर हुआ ये गेंदबाज

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन को पीठ की चोट के कारण कम से कम आगली गर्मियों तक टीम से बाहर कर दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ न्यूजीलैंड के पहले टेस्ट के बाद तेज गेंदबाज को स्कैन के लिए भेजा गया था जहां उनकी पीठ के उसी हिस्से में स्ट्रेस फ्रैक्चर मिला जहां पिछले साल जैमीसन का ऑपरेशन किया गया था। चिकित्सकों के अनुसार उन्हें दूसरी सर्जरी कराने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन चोट को ठीक होने के लिये आराम और पुनर्वास की जरूरत होगी।

आईसीसी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि तेज गेंदबाज अब तक मिले समर्थन के लिए आभारी है। जैमीसन ने कहा 'पिछले कुछ दिन मेरे लिए सबसे चुनौतीपूर्ण रहे हैं लेकिन मैं अपने साथी, परिवार, टीम के साथियों, सहयोगी स्टाफ और चिकित्सा पेशेवरों से मिले समर्थन के लिए बेहद आभारी हूँ। मुझे पता है कि एक क्रिकेटर के रूप में चोटें जीवन का हिस्सा हैं और मेरी उम्र में मुझे उम्मीद है कि मेरे पास अभी भी खेलने



के कई दिन बाकी हैं। न्यूजीलैंड के कोच गैरी स्टीड ने कहा 'हम सभी ने देखा है कि काइल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी के लिए कितनी मेहनत की है और उनके लिए इस तरह का झटका मिलना कठिन है। सकारात्मक पक्ष पर,

हम जानते हैं कि वह न्यूजीलैंड के लिए क्रिकेट खेला जारी रखने के लिए कितने दृढ़ हैं और पुनर्वास की राह पर हम पूरी तरह से उनके साथ होंगे। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला 2-0 से जीती।

युवराज सिंह के घर लाखों की चोरी, मां शबनम सिंह ने इन पर जताया शक



पुलिस को शबनम सिंह ने बताया कि वे सितंबर 2023 से गुडगांव स्थित दूसरे घर में रह रही थीं। 5 अक्टूबर 2023 को जब वह पंचकुला के घर लौटी तो पहली बार अलमारी से करीब 75 रुपये और ज्वेलरी समेत अन्य सामान गायब होने का पता चला। इसके बाद उन्होंने खुद जांच करने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी सुराग उनके हाथ नहीं लगा। हालांकि उन्होंने यह नोट किया कि ललित देवी और सिलदार पाल अचानक नौकरी छोड़कर दिवाली से गायब हैं।

एसएचओ बोले- ...तो चोरों तक कैसे पहुंचेंगे

उन्होंने इन दो पूर्व कर्मचारियों पर ही चोरी का शक जताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस मामले में एसएचओ थाना मनसा देवी ने कहा कि अगर हम मीडिया को सब कुछ बता ही देंगे तो चोरों तक कैसे पहुंच सकेंगे? उन्होंने कहा कि पुलिस गंभीरता से इस मामले को सुलझाने में जुटी है।

झोन और रूट तय कर संचालन किया जाएगा, जल्द पॉलिसी बनेगी

शहर की सड़कों पर जाम की स्थिति बनती रहती है, 9500 ई-रिक्शा रजिस्टर्ड है उज्जैन शहर में

सिंहस्थ लोक ♦ उज्जैन

शहर में 9500 रजिस्टर्ड ई-रिक्शा है। इनकी वजह से सड़कों पर जाम की स्थिति बन रही है। शहर में यातायात व्यवस्थित रहे और नागरिकों को लोक परिवहन की सुविधा भी मिलती रहे। इसे ध्यान में रखकर ई-रिक्शा का संचालन झोन और रूट तय कर किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही पॉलिसी बनेगी।

जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्टर नीरज कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में यातायात व्यवस्था की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि ई-रिक्शा की वजह से महाकाल लोक के आसपास सुबह के वक्त लगातार जाम की स्थिति बन रही है। आरटीओ द्वारा बताया गया कि शहर में पंजीकृत ई-रिक्शा की संख्या लगभग 9500 है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि ई-रिक्शा को विभिन्न झोन में डिवाइड किया जाये।

इनका विधिवत रूट तैयार किया करें। झोन की अलग-अलग कलर कोडिंग करवाई जाए। झोन क्रमांक ई-रिक्शा के पीछे अनिवार्य रूप से अंकित करें। इसके लिए उप समिति बनाकर अलग-अलग झोन के अनुसार ई-रिक्शा के रूट तैयार किए जाएंगे। कलेक्टर ने यह कार्य अगले एक सप्ताह



में पूरा किया करना है। समस्त ई-रिक्शा चालकों को आई कार्ड प्रदाय किए जाए। चालकों को निर्देश दिए जाए कि वे अनिवार्य रूप से युनिफार्म पहनें।

होम स्टे की जांच करें- कलेक्टर ने निर्देश दिये कि शहर में बिना पंजीयन के जो भी होम स्टे संचालित किए जा रहे हैं, उनकी जांच कराई जाए। यह सुनिश्चित करें कि होम स्टे के लिए निर्धारित मापदण्डों को पूरा किया जा रहा है

अथवा नहीं। होम स्टे के पंजीयन के लिये कैम्प लगाये जाए। होम स्टे के समीप वाहन पार्किंग की क्या व्यवस्था है, इसकी जांच की जाए। यह देखें कि होम स्टे में बाहर से आने वाले लोगों के वाहनों के कारण यातायात में किसी भी तरह का व्यवधान तो नहीं हो रहा है, पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने कहा कि ट्रेवल वेब साइट्स पर शहर में संचालित जितने भी पंजीकृत होटल और होम स्टे हैं, उनका अधिकृत रूप से मोबाइल नम्बर वेब साइट पर उपलब्ध कराने की सलाह जारी की जाए। शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि बाहर से आने वाले थ्रडपार्टी ऑनलाइन होटल और होम स्टे में बुकिंग करते हैं, परन्तु यहाँ आने पर उन्हें वह स्थान नहीं मिलता है।

मालवाहक गाड़ियों के प्रवेश समय तय होगा- शहर के बाजार में मालवाहक गाड़ियों द्वारा लोडिंग और अनलोडिंग व्यवस्था की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने कहा कि व्यापारी एसोसिएशन के साथ बैठक आयोजित की जाए। भारी/हल्के मालवाहक गाड़ियों के शहर में प्रवेश का समय निर्धारित किया जाए।

हाथदेलों पर कार्रवाई के निर्देश- विभिन्न स्थानों पर अनाधिकृत रूप से लगाये जा रहे हाथदेलों पर नगर पालिक निगम को कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

प्रोग्राम और हरसिद्धि चौराहे पर जगह-जगह हाथ डेले लगा दिये जाते हैं। इस वजह से यातायात में बहुत परेशानी होती है। कलेक्टर ने कहा कि नगर निगम द्वारा संयुक्त टीम बनाई जाकर कार्यवाही की जाये। एक ही रूट पर चलने वाली बसें नानाखेड़ा बसस्टेण्ड से संचालित की जायें।

हरिफाटक रोटी को छोटा करने का सुझाव- बैठक में बताया गया कि हरिफाटक चौराहे से गऊघाट तरफ जाने वाले मार्ग पर एक गेट बना हुआ है, जिसकी वजह से यातायात में व्यवधान उत्पन्न होता है। कलेक्टर ने जांच कर उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। हरिफाटक चौराहे पर निर्मित रोटी को छोटा किये जाने पर विचार-विमर्श किया गया। कलेक्टर ने इस पर कहा कि यातायात सलाहकार को बुलाकर इसकी समीक्षा की जाए। उचित कार्यवाही की जाये। नागदा-खाचरोद में फर्नाखेड़ी पर चिन्हित ब्लेकस्पॉट का परिशोधन किये जाने के निर्देश दिये गये। कलेक्टर ने कहा कि ब्लेकस्पॉट के 200 मीटर पहले से रम्बल स्ट्रीप लगाई जाए। नागझिरी स्थित ब्लेकस्पॉट का भी शीघ्र-अतिशीघ्र परिशोधन किये जाने के निर्देश दिए गए। कालभैरव मार्ग पर अतिरिक्त स्टापेज बनाये जाने के लिये कहा गया। बेगमबाग से नीलकंठ वन की तरफ जाने वाले मार्ग पर स्लाइडिंग गेट बनाये जाने का प्रस्ताव दिया गया।

सीएम यादव बोले- अध्यात्मिकता की यात्रा ही भारत की विकास यात्रा

सिंहस्थ लोक ♦ उज्जैन

हे भारत आध्यात्मिकता से विश्व विजयी बनो। यह विमर्श हमारा मूल दृष्टिकोण है। हम मूलतः आध्यात्मिक हैं। हमारा मूल दृष्टिकोण आध्यात्मिक है। सम्पूर्ण प्रकृति में परमेश्वर निहित है। उसे बस आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। उक्त विचार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने माधव सेवा न्यास में विवेकानन्द केन्द्र कन्याकुमारी मध्य प्रान्त के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारे इतिहास में हमारा प्राचीन ज्ञान-विज्ञान समाहित है। कुंभ का मेला नक्षत्र के अनुसार होता है। प्रत्येक बारह वर्ष में उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन किया जाता है। बाकी जगह आयोजित होने वाले मेले को कुंभ कहा जाता है, लेकिन उज्जैन में आयोजित होने वाले कुंभ को सिंहस्थ कहा जाता है। सिंहस्थ में विवेकानन्द एवं रामकृष्ण मिशन के मानने वाले भी आते हैं। परमेश्वर पूरी सृष्टि में विद्यमान है। डॉ. यादव ने कहा कि आध्यात्मिकता की यात्रा ही भारत की विकास यात्रा है। उज्जैन में स्थित डोंगला में स्टैंडर्ड टाइम की गणना होती है। विमर्श कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने एकनाथ रनाडे के विचारों पर विवेकानन्द केन्द्र कन्याकुमारी के विद्यार्थियों द्वारा लिखित पुस्तक ध्याननिष्ठ जीवन का विमोचन किया। इस अवसर पर रिस्ता दीदी ने



तीन ओंकार प्रार्थना की प्रस्तुति दी। नन्दन जोशी ने सभी अतिथियों का परिचय दिया। मानस भट्टाचार्य ने एकल गीत का गायन किया।

आध्यात्मिकता केवल उपासना तंत्र नहीं - पद्मश्री डॉ. भिड़े

विवेकानन्द केन्द्र कन्याकुमारी की उपाध्यक्ष पद्मश्री डॉ.निवेदिता भिड़े ने कहा कि आध्यात्मिकता केवल एक उपासना तंत्र नहीं है, अपितु आध्यात्मिकता के सम्बन्ध में भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है कि स्वभाव ही आध्यात्मिकता है। अपनेपन के दायरे

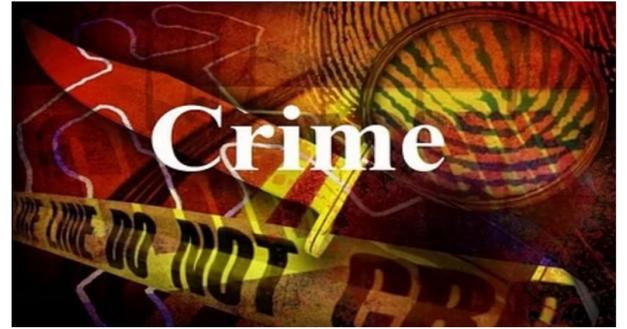
में जो आता है, वह आध्यात्मिकता है। जो व्यक्ति परिवार, समाज और देश के बारे में सोचता है, वह आध्यात्मिकता ही है। व्यक्ति का विस्तृत स्वरूप परिवार है। परिवार का विस्तृत स्वरूप समाज है। समाज का विस्तृत स्वरूप राष्ट्र है और राष्ट्र का विस्तृत स्वरूप ही सम्पूर्ण विश्व है। व्यक्ति अपना स्वाभाविक जीवन जीते हुए निःस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करता है, वह सब आध्यात्मिकता ही है। इस दौरान प्रबंध निदेशक इंजीनियरिंग प्रा. लि. के प्रतीक पटेल ने कहा कि उज्जैन में जब से महाकाल लोक बना है, तब से उज्जैन का आर्थिक विकास उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है।

हफ्ता नहीं देने पर हिस्ट्रीशिर बद्माश ने ढाबा संचालक पर चाकू से किया हमला

सिंहस्थ लोक ♦ उज्जैन

उज्जैन जिले की इंदौर रोड पर हफ्ता नहीं देने पर शनिवार देर रात हिस्ट्रीशिर बद्माश ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर ढाबा संचालक पर चाकू से हमला कर दिया। हमें में ढाबे संचालक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, पुलिस ने केस दर्ज कर बद्माश की तलाश शुरू कर दी है। प्रारंभिकी जांच में सामने आया है कि बद्माश ने 21 जनवरी को भी ढाबा संचालक पर हमले का प्रयास किया था। नानाखेड़ा थाना पुलिस ने बताया कि इंदौररोड हाइवे पर रविंद्र पिता दरबारसिंह राठौर वृद्धवन ढाबा संचालित करता है। बीती रात बाइक से आए चार बद्माशों ने रविन्द्र पर चाकू से हमला कर दिया। सूचना पर पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक बद्माश भाग गए। घायल रविन्द्र को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया और उसके बयान दर्ज कर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

घायल ढाबा संचालक रविन्द्र ने बताया कि 21 जनवरी को कोकलाखेड़ी के रहने वाले



बद्माश नागेंद्र उर्फ नागू ने शराब पीने के लिए पैसे मांगे थे। नहीं देने पर चाकू की मूठ से मारपीट कर घायल कर दिया था। जिसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई थी। शनिवार देर रात नागेंद्र अपने तीन साथियों के साथ ढाबे पर आया और चाकू से हमला कर दिया, नागेंद्र के साथियों ने उसके साथ लात-पूसों से जमकर मारपीट की। उनके पास पिस्टल भी थी। बद्माश और उसके साथियों को मारपीट करता देख ढाबा पर काम करने वाले

लोगों ने बीच बचाव किया। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए, इस दौरान एक बद्माश अपनी बाइक छोड़ गया, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। मारपीट की यह घटना ढाबे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज के आधार पर पुलिस बद्माश के साथियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। पुलिस का कहना है कि बद्माशों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

चार साल बाद आया फैसला, महिला की हत्या करने वाले को मिला आजीवन कारावास

सिंहस्थ लोक ♦ उज्जैन

उज्जैन में उधार रुपयों को लेकर हुई महिला की हत्या के मामले में चार साल बाद न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने हत्या के बाद महिला का शव झाड़ियों में फेंक दिया था।

बता दें कि नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के आलमपुर उड़ाना में अक्टूबर 2019 को झाड़ियों से एक महिला का शव बरामद हुआ था। पहचान सुनीता पति राकेश यादव (40) निवासी धनलाल की चाल के रूप में हुई थी। परिजनों के बयान दर्ज करने पर पति ने बताया था कि सुनीता ने नरवर में रहने वाले आजाद पटेल से रुपये उधार लिये थे। दो दिन पहले वह घर आया था और रुपये नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देकर गया था। उसके बाद पत्नी सुनीता लापता हो गई थी।

पुलिस ने पति के संदेह और



पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से हत्या का खुलासा होने पर नरवर में रहने वाले आजाद पति इदा पटेल को गिरफ्तार कर पूछताछ की। उसने हत्या करना कबूल कर लिया था। पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। चार साल चली सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपेश तिवारी ने आरोपी को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रकरण में पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेवर और उमेश सिंह तोमर द्वारा की गई।

तैयारी: टीडीएस कटने के बाद रिटर्न भरना जरूरी होगा...

सिंहस्थ लोक ♦ उज्जैन

उज्जैन जिन करदाताओं ने टीडीएस कटने के बाद भी आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उन्हें जल्द ही आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है। ऐसे मामलों में सख्ती करने की तैयारी की जा रही है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के मुताबिक टीडीएस कटने के बाद रिटर्न न जमा करने वाले ऐसे करदाताओं की संख्या करीब 1.5 करोड़ है। विभाग केवल उन्हीं को नोटिस भेजेगा, जिनके बारे में उसके पास निश्चित जानकारी है। आयकर विभाग के पास बड़ी मात्रा में डाटा मौजूद है, जिसकी मदद से वह गड़बड़ी का पता लगा पा रहा है। अगर करदाता से कोई ब्योरा भरने से रह गया है तो उन्हें नोटिस के माध्यम से सूचित किया जा रहा है और रिटर्न को अपडेट करने के लिए कहा जा रहा है। विभाग ने ऐसे 51 लाख अपडेटेड रिटर्न से अब तक 4600 करोड़ रुपये इका किए हैं।

इनके लिए जरूरी : नए नियमों के तहत आईटीआर-2 में आयकरदाताओं को कानूनी इकाई पहचानकर्ता (एलआईआई) का विवरण देना होगा। इसके तहत राजनीतिक दलों को दिया गया चंदा, जिसमें भुगतान की तारीख और तरीका शामिल है। इसके अलावा दियोग व्यक्तिके आश्रित के चिकित्सा उपचार सहित भरण-पोषण के लिए दावा की गई किसी भी कटौती की जानकारी आदि शामिल है।



आग से निपटने के इंतजाम नाकाफी वर्षों से नहीं बना नया फायर स्ट्रक्चर

सिंहस्थ लोक ♦ उज्जैन

हरदा में हुए कांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। प्रदेश या देश में जब कोई बड़ा हादसा होता है तभी व्यवस्था की हकीकत सामने आती है। ऐसा ही हाल शहर के फायर ब्रिगेड का है। हरदा हादसे के बाद जब इसकी हकीकत जानी तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। शहर का रेडियस काफी बड़ चुका है,लेकिन फायर स्ट्रक्चर उस हिस्सा से नहीं है।

अभी शहर में सिर्फ एक फायर स्टेशन है। इसके बाद कोई भी नया फायर स्टेशन तैयार नहीं किया गया, जबकि वर्तमान में शहर की रेडियस १० से १५ किमी तक पहुंच गई है। इस लिहाज से तो कम से कम ४ और फायर स्टेशन की जरूरत है। इतना



ही नहीं फायर गाड़ियों की उम्र भी पूरी होने के साथ उनकी कार्यक्षमता भी कम हो चुकी है। शहर में हर साल 10 से ज्यादा बड़ी और मध्यम-छोटी घटनाएं सेकड़ों घटनाएं होती हैं। शहर के मुख्य बाजारों में बनी ऊंची इमारतों में अग्नि सुरक्षा के इंतजामों को टटोला तो व्यवस्था और जरूरत के बीच बड़ा

गैप नजर आया। पाया कि उज्जैन में आग बुझाने के इंतजाम नाकाफी हैं। कई बहुमंजिला इमारतों में आपात स्थिति से निपटने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं है। 30 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर आग बुझाने को तो फायर ब्रिगेड के पास संसाधन ही नहीं है।

15 साल से भर्ती नहीं फायर स्टेशन पर बल की भी कमी है। फायर में निरीक्षक, चालक प्रधान आरक्षक से लेकर आरक्षक फायरमैन की जरूरत है, लेकिन पिछले 15 सालों से भर्ती नहीं हुई है। शासन ने यहां लीड फायरमैन, फायरमैन, ड्राइवर के 150 पद स्वीकृत कर रखे हैं। स्थायी नियुक्ति सिर्फ 15 कर्मचारियों की ही है। शेष 40 कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी एवं टेका प्रणाली पर नियुक्त है। सूत्रों के अनुसार इनमें से कई अनफिट हैं।

पिछले हिस्से में चल रहे निर्माण कार्य रोकें

उज्जैन संभाग के सबसे बड़े जिला अस्पताल भवन टूटेगा..?

सिंहस्थ लोक ♦ उज्जैन

उज्जैन तत्कालिन सिंधिया रियासत द्वारा बनाया गया भव्य जिला अस्पताल का भवन टूटेगा। भवन के टूटने को लेकर जहां अलग-अलग कयास लगाए जा रहे हैं वहीं इस बात का आधिकारिक रूप से न तो खण्डन किया जा रहा है और न ही बताया जा रहा है कि आखिर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की मंशा क्या है? उज्जैन संभाग के सबसे बड़े अस्पताल, जिसे जिला या सिविल अस्पताल कहा जाता है का विशाल भवन आज भी अपनी जगह मजबूती से खड़ा हुआ है। भू-तल और प्रथम तल पर प्रारंभिक रूप से चार वाडों से शुरू यह अस्पताल बाद में विस्तार लेते गया। यहां उस समय का सबसे आधुनिक ऑपरेशन थियेटर बना वहीं लिफ्ट भी लगी। बाद में पिछले हिस्से में विस्तार होकर तैर और हड्डी वाड बनाया गया,जोकि भू और प्रथम तल पर संचालित होते रहे। परिसर में ही तत्कालिन समय बनी ओपीडी है। जहां सुबह और शाम को आपातकालीन केस आते हैं तथा यहीं पर इंजेक्शन/मायनर सर्जरी का काम होता है। समीप में सेटी भवन है, जिसमें विशेषज्ञ ओपीडी, फिजियोथेरेपी, दवाई वितरण का काम होता है। इस भवन के पीछे पोस्टमार्टम भवन बना हुआ है। टी.बी. की करोड़ों रुपए में बनने वाली लेब का काम रोवा।



ऐसे हुआ चर्चाओं का दौर शुरू- मुख्य भवन के पिछेवाले हिस्से में 50 बिस्तर का आधुनिक आयसीयू बनाया शुरू हुआ। समीप में 100 बिस्तर के भवन का विस्तार होना था। गड्डे खोदे गए थे और ठेकेदार ने पिल्लर उठा दिए थे। यह काम भी रोक दिया गया। साथ ही सेटी भवन के प्रथम तल पर टी.बी. की जांच की संभाग की सबसे बड़ी और उन्नत लेब जोकि करोड़ों रूपए में बननेवाली थी,उसका काम रोक दिया गया। इधर माधवनगर अस्पताल में परदे के पिछे से निर्देश पहुंचे कि जिला अस्पताल के वाड शिफ्ट होंगे, व्यवस्थाएं बनाओ।

इनका कहना है- इस संबंध में सिविल सर्जन डॉ.पी.एन.वर्मा से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि-पिछले माह भोपाल से एसीएस सुदाम खड़े आए थे। उन्होंने मौके का अवलोकन किया। कलेक्टर भी उनके साथ थे। श्री खड़े ने निर्देश दिए कि मेडिकल कॉलेज के उपयुक्त अस्पताल भवन बनाया जाए,जोकि चरक भवन से कमतर न हो। इसके लिए कार्ययोजना बनाई जाए। यह योजना जिला प्रशासन बना रहा है। उसी समय से काम रोक दिया गया है। हालांकि हमें कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है कि जिला अस्पताल भवन तोड़ा जाना है और नया भवन बनेगा। लेकिन कुछ तो हो रहा है। भोपाल से अधिकृत निर्देश/जानकारी आने पर स्थिति स्पष्ट होगी।

महाकाल के आंगन में मिला था एक हजार साल पुराना शिव मंदिर, पुनर्निर्माण शुरू



सिंहस्थ लोक ♦ उज्जैन

ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में भूभ्रंश से प्राप्त हुए एक हजार साल पुराने शिव मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग द्वारा पुरावशेषों को व्यवस्थित कर स्ट्रक्चर के आसपास साफ सफाई कराई जा रही है। जल्द ही कुशल कारीगर भूमिज शैली में मंदिर का निर्माण करेंगे।

मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग की योजना के अनुसार मंदिर की ऊंचाई 37 फीट रहेगी। यह मंदिर पूर्व में भूमिज शैली में बना था। इसका नवनिर्माण भी इसी शैली में होगा। मंदिर निर्माण में करीब डेढ़ साल का समय लगेगा। मंदिर निर्माण की अनुमानित लागत करी 70 लाख रुपये रहेगी।

निर्माण समिति का गठन

मध्य प्रदेश पुरातत्व आयुक्त उर्मिला शुक्ला ने पुरातत्व अधिकारी डारमेश यादव के नेतृत्व में निर्माण समिति का गठन किया है। शोध अधिकारी डा.ध्रुवेंद्र जोधा की देखरेख में निर्माण कराया जाएगा। डा.जोधा अब प्रदेश के

कई मंदिरों का पुनर्निर्माण करा चुके हैं। मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग के अनुसार इस मंदिर को उज्जैन संभाग के पहले पुनर्निर्मित होने वाले मंदिर का गौरव प्राप्त होगा।

तीन साल पहले खोदाई में मिला था मंदिर

महाकाल मंदिर में नवनिर्माण के लिए की जा रही खोदाई के दौरान साल 2021 में जमीन से करीब 28 फीट नीचे एक शिव मंदिर प्राप्त हुआ था। एक हजार साल पुराने इस शिव मंदिर के आधार भाग के आसपास ही इसके भूभ्रंश अवशेष भी बिखरे हुए थे। साथ ही शिवलिंग, नंदी, भगवान गणेश, विष्णु तथा देवियों की मूर्तियां भी मिली थीं। उखनन का सारा काम शोध अधिकारी डा.ध्रुवेंद्र जोधा के निदेशन में हुआ। पुरासाक्ष्यों तथा इसके धार्मिक व पौराणिक महत्व को देखते हुए पुरातत्व विभाग ने राज्य शासन व मंदिर प्रबंध समिति के सहयोग से इसके पुनर्निर्माण की योजना बनाई, जो मूर्त रूप लेने लगी है।

उज्जैन में जुटे 270 विवि के कुलपति

राज्यपाल बोले- बंधन मुक्त शिक्षा देने हुई नई शिक्षा नीति की शुरुआत



सिंहस्थ लोक ♦ उज्जैन

प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल शुक्रवार को उज्जैन में थे। उन्होंने विद्यार्थियों के बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा और चुनौतियां कार्यक्रम में शिरकात की। उन्होंने नई शिक्षा नीति पर भी छात्रों से संवाद किया। इसके पहले राज्यपाल मंगु भाई पटेल ने यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सौजन्य से आयोजित राष्ट्रीय कॉफ्रेंस का दीप प्रज्वलन शुभारंभ किया। राज्यपाल पटेल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का निर्धारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाने के साथ बंधन मुक्त शिक्षा का अवसर देने के संकल्प के साथ नई शिक्षा नीति का निर्माण कराया है। नई शिक्षा नीति में कला और विज्ञान व्यावसायिक और शैक्षणिक योग्यता पठन और गैर पठनकर गतिविधियों के बीच विभाजन को खत्म करने का अवसर उपलब्ध कराया है। इसमें विद्यार्थी को पसंद के क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त का अवसर और प्रेरणा मिलेगी। नई शिक्षा नीति के लागू होने से शिक्षण में बहुमुखी माहौल को बढ़ावा मिलेगा।

यूजीसी के चेयरमैन ने बताया- क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति

यूजीसी के चेयरमैन प्रो. एम. जगदीश ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यूजीसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन को पूरा करने के लिए सतत प्रयास कर रहा है। आयोग यह सुनिश्चित करता है कि उपरोक्त पहल के लाभ महत्वाकांक्षी युवाओं के एक बड़े वर्ग मिल सकें। महत्वपूर्ण पहल के प्रभावी कार्यान्वयन और एक रोड मैप विकसित करने में विश्वविद्यालयों को सुविधा प्रदान करने के लिए यूजीसी ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों और मानित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों सहित पांच क्षेत्रीय समितियों का गठन किया है।

कॉफ्रेंस के शुभारंभ के बाद सुबह से लेकर शाम तक 10 सत्र आयोजित किए गए। यह सत्र विश्वविद्यालय के शालाका दीर्घा, विधि अध्ययनशाला के कक्षाओं में कार्यक्रम में शामिल होने वाले कुलपति अलग-अलग चर्चा कर नई शिक्षा नीति को लागू करने पर आ रही परेशानी को लेकर भी सुझाव दिए।

भिक्षावृत्ति से मुक्त हो उज्जैन, मकान और गाड़ी के मालिक फिर भी मांग रहे भीख

सिंहस्थ लोक ♦ उज्जैन

ज्योतिर्लिंग महाकाल की नगरी उज्जैन में भिक्षावृत्ति को ज्यादातर लोगों ने जरूरत की बजाय पेशा बना लिया है। इस पेशे में बिना किसी शारीरिक या मानसिक श्रम किए दिनभर में हजार-दो हजार रुपये की आमदनी होने से कुछ लोगों ने अपने बच्चों तक को इस कार्य में जबरिया धकेल दिया है। इनमें से कुछ तो पक्के मकान और गाड़ी के मालिक भी हैं।

कुछ दो-तीन पीढ़ियों से ये कार्य कर रहे। वे पुनर्वास की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी ले रहे। निजी तौर पर ये अपनी जिंदगी से खुश हैं मगर देश-दुनिया से उज्जैन घूमने आए पर्यटक और वो दुकानदार परेशान हैं, जो जोर-जबदस्ती के शिकार होते।

इन सब विसंगतियों के बीच अच्छी बात ये है कि उज्जैन को भिक्षावृत्ति मुक्त करने को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने एक बार फिर कदम उठाया है। वो कदम, जो महाकुंभ सिंहस्थ- 2016 के पहले भी उठाया था। जिसका कुछ असर भी दिखाई भी दिया था मगर सरकार और समाज का ध्यान भटकने से स्थितियां फिर प्रतिकूल होती चली गईं।

ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के नवविस्तारित क्षेत्र 'श्री महाकाल महालोक' के बनने के बाद तो भिक्षावृत्ति करने वालों की संख्या भी काफी बढ़ गई। नगर निगम एक्ट में भिक्षावृत्ति रोकने का प्रावधान है। उज्जैन में इस कार्य का नोडल अधिकारी अभी कुछ दिन



पहले ही नगर निगम आयुक्त आशीष पाठक ने सहायक आयुक्त प्रदीप सेन को बनाया है।

केंद्र सरकार ने उज्जैन को भिक्षावृत्ति मुक्त करने के लिए संस्था प्रवेश के नाम से प्रसिद्ध परम पूज्य रक्षक आदिनाथ वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसायटी को जिम्मेदारी दे रखी है। संस्था की संस्थापक अध्यक्ष सापटवेयर इंजीनियर रूपाली जैन हैं, जो अपनी संस्था

के बैनर तले इस जिम्मेदारी का निर्वहन पड़ोसी इंदौर शहर में कई महीनों से कर रही हैं।

उन्होंने बताया कि सतही सर्वे पिछले वर्ष एक ड्राफ्ट केंद्र सरकार को भेजा था जो स्वीकृत हुआ है। अब उज्जैन में जियो टैगिंग बेस्ड डिटेल् सर्वे किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक भिक्षुक के नाम, उम्र, पते, बैंक अकाउंट नंबर सहित समस्त जानकारी होगी।

उज्जैन विक्रमोत्सव में जुबिन नौटियाल और हेमा मालिनी जमाएंगे रंग

सिंहस्थ लोक ♦ उज्जैन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक मार्च को उज्जैन में विक्रमोत्सव, महाशिवरात्रि एवं नगर गौरव दिवस भव्य रूप में मनाये जाने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर व्यापार मेला और इन्वेस्टर्स समिट का भी आयोजन होगा। उज्जैन की विक्रम व्यापार मेले का समापन 9 अप्रैल 2024 को शिवज्योति आर्षण कार्यक्रम के साथ किया जाएगा। इन आयोजनों से उज्जैन में पर्यटन के साथ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सांस्कृतिक आयोजनों में प्रसिद्ध अभिनेत्री एवं नृत्यांगना हेमा मालिनी और जुबिन नौटियाल और अभिमत त्रिवेदी के कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। इस मौके पर 'पौराणिक फिल्म फेस्टिवल' भी होगा। साथ ही विक्रम कैलेंडर और वैदिक षष्ठी का लोकार्पण भी होगा।

व्यापार मेले का आयोजन

उज्जैन में उज्जैन की विक्रम व्यापार मेले की तैयारियां भी की जा रही हैं। व्यापार मेले का आयोजन नगर निगम उज्जैन द्वारा किया जा रहा है। व्यापार मेले में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की दुकानें प्रमुख रूप से लगाई जायेंगी। इनमें उज्जैन के स्थानीय व्यापारियों को वरीयता दी जा रही है। व्यापार मेले के अन्य सेक्टरों में विभिन्न वस्तुओं के डीलर्स को भी आमंत्रित किया जा रहा है। मेले में नागरिकों के लिये फूड जॉन भी रहेगा। इस जॉन में विशेष रूप से मालवा के व्यंजनों का लुत्फ नागरिक उठा सकेंगे। व्यापार मेले में पर्यटन, संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के माध्यम से वस्तुओं का प्रदर्शन और बिक्री की जायेगी। व्यापार मेले का समापन 9 अप्रैल को होगा।

इन्वेस्टर्स समिट का भी कार्यक्रम

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर उज्जैन के साथ संभाग के अन्य जिलों में उद्योगों को आकर्षित करने के लिये इन्वेस्टर्स समिट भी आयोजित की जा रही है। समिट में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्यों के निवेशकों को आमंत्रित किया जा रहा है। समिट में गारमेंट्स, टेक्स्टाइल और फूड प्रोसेसिंग यूनिट के जरिये

स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं। सभी आयोजनों के लेकर उज्जैन में व्यापक तैयारियां चल रही हैं। आयोजन की प्रस्तावित गतिविधियों की सूची बनाई जा रही है। इन्वेस्टर्स समिट में आमंत्रित उद्योगपतियों और उनकी उद्योग इकाइयों की जानकारी अपडेट की जा रही है। एक मार्च को विक्रम व्यापार मेला, इन्वेस्टर्स समिट और विक्रमोत्सव के भव्य आयोजन की तैयारियों की पिछले दिनों सचिव एमएसएमई श्री पी. नरहरि और एमपीआईडीसी के एमडी ने स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा की।

स्वच्छता और सुरक्षा पर जोर

उज्जैन में एक मार्च से होने वाले आयोजनों में नागरिकों के सुविधाजनक आवागमन के साथ व्यापार मेला स्थल पर नगर निगम का स्वच्छता और सुरक्षा पर विशेष ध्यान रहेगा। संपूर्ण मेला क्षेत्र सीसीटीवी कैमरों से कवर रहेगा। मेला स्थल पर पार्किंग की व्यापक व्यवस्था रहेगी। व्यावसायियों के लिये गोडाउन की व्यवस्था भी की गई है। इन आयोजनों में जन-भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।



होटलों में रियायती दर पर रुकने की सुविधा

ऑटोमोबाइल की खरीदी पर टेक्स में राज्य शासन द्वारा 50 प्रतिशत दी जा रही छूट का लाभ नागरिक प्राप्त कर सकेंगे। व्यापार मेले में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से जुड़ी कंपनी अपने प्रोडक्ट को व्यापार मेले में लॉन्च कर सकेंगी। उज्जैन जिला प्रशासन नगर पालिका उज्जैन अन्य शासकीय विभागों के साथ मिलकर एक मार्च से पीजीबीटी कॉलेज मैदान एवं दशहरा मैदान में 8 हेक्टेयर एरिया में आयोजन करने जा रहा है। यहां करीब 400 से अधिक दुकानें लगाई जाएंगी। 220 दुकानें पीजीबीटी मैदान में और 181 दुकानें दशहरा मैदान में संचालित होंगी। पर्यटन विभाग महाकाल दर्शन के साथ होटलों में रियायती दर पर रुकने की सुविधा उपलब्ध करायेगा।

विष्णु सागर व विक्रम सरोवर संवारेंगे

एसटीपी लगेंगे जियो लाइट पत्थर व जलीय पौधों से शुद्ध रहेगा पानी

सिंहस्थ लोक ♦ उज्जैन

शहर के तालाब व सागरों को संवारने की दिशा में कदम आगे बढ़ने लगे हैं। जल्द ही विष्णु सागर व विक्रम सरोवर एक नए स्वरूप में दिखने लगे। पर्यटकों का जुड़ाव व खिंचाव यहां बना रहे, इस लिहाज से दोनों स्थलों को संवारने में शुद्धता का खास ख्याल रखा गया है। ये कि दोनों तालाब पर एसटीपी से ट्रीट किया हुआ पानी छोड़ा जाएगा। इसके बाद ही पानी हमेशा 12 महीने साफ रहे, बटबू न मारे, इसके लिए जियो लाइट पत्थर व विशेष प्रकार के जलीय पौधों का उपयोग होगा।

श्रीराम जनार्दन मंदिर के पास स्थिति विष्णु सागर के कुल 49210.00 स्क्वियर मीटर क्षेत्र का डेवलपमेंट करीब 5.50 करोड़ की लागत से होगा, जबकि देवास रोड के विक्रम परिसर स्थित विक्रम सरोवर को संवारने में करीब 3 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यहां 20593.00



स्क्वियर मीटर में डेवलपमेंट होगा। यह कार्य मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के तहत होने जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये स्थल पर्यटन के रूप में उभरेंगे और परिवार के साथ घूमने के लिए एक

सार्वजनिक स्थान के रूप में पहचाने जाएंगे। लोगों को यहां ताजी हवा और साफ पानी में समय बिताने को मिलेगा। तालाबों के डेवलपमेंट के लिए डिजाइन तैयार करने वाले कंसल्टेंट सुरूर सक्सेना ने बताया कि नगर

निगम ने इन कामों के लिए टेंडर आमंत्रित कर लिए हैं। उम्मीद है कि टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही काम होने लगे।

चारों तरफ बाउंड्रीवाल रहेगी। सोलर प्लांट, ताकि बिजली की आपूर्ति यहीं से हो सकेगी। सुरक्षा की दृष्टि से चारों तरफ बाउंड्रीवाल। विक्रम सरोवर में प्लांटेशन के बीच पुलिया निर्माण भी। तरह-तरह के फूलों की क्यारी। पांथ-वे, पार्किंग, बैठक स्थल। डग हाउस बनेगा। यहां बलखों को प्राकृतिक वातावरण मिलेगा। बरसाली नालों के पानी को एसटीपी से ट्रीट करके तालाब में छोड़ेंगे। इस पानी की जैविकता बनी रहे, इसके लिए तालाब में जियो लाइट पत्थर व जलीय पौधों की बाल रहेगी। इससे पानी सदा साफ और जलीय जीवों के लिए उपयुक्त रहेगा। आकर्षण की दृष्टि से तालाब में फाउंटेन भी रहेगी। रात्रि में इनकी सुंदरता बढ़ेगी। नौकायान आदि। आकर्षक प्लांटेशन सेल्फी पॉइंट बनेगा। बारिश व धूप से बचाव के लिए शेड रहेगी।